सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 09, नई दिल्ली । शुक्रवार, 22 मार्च 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते।

03 रामायण से जुड़ी जगहों के लिए आईआरसीटीसी लाया स्पेशल श्रीलंका टूर

06 सेहत को समझिए साहब'

08 वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट पर है कई रहस्यों का भंडार

खत्म हो जाएं टोल प्लाजा तो होगी हजारों करोड़ रुपये की बचत, समय-ईंधन और पैसों का हो रहा भारी नुकसान

संजय बाटला

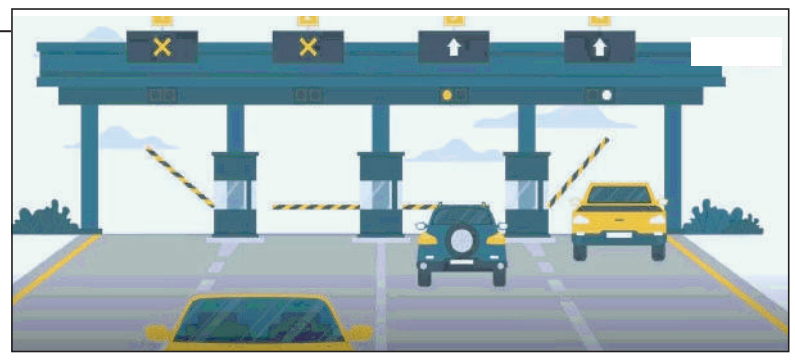

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने की राह में टोल प्लाजा सबसे बड़ी बाधा हैं। टोल प्लाजा की वजह से एनसीआर एक यूनिट की तरह नहीं दिखता है। एनसीआर के शहरों से दिल्ली में प्रवेश करने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं दिल्ली से बाहर निकलते ही कुछ दूरी पर टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल प्लाजा पर पीक आवर में ही नहीं बल्कि, बाकी समय के दौरान भी वाहनों का दवाब रहता है। इससे इनकी लेनों में लाइनें लगी रहती हैं।

टोल प्लाजा कर रहे समय, ऊर्जा और पैसों का भारी नुकसान

कुल मिलाकर टोल प्लाजा की वजह से समय, ऊर्जा यानी ईंधन और पैसे का भारी नुकसान हो रहा है। एनसीआर देश का सबसे विकसित क्षेत्र बने, इसके लिए टोल प्लाजा से मुक्ति दिलानी होगी। टोल प्लाजा से मुक्ति मिलने से ही रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आकांक्षी एनसीआर का सपना साकार हो सकेगा। केवल हाईवे या एक्सप्रेस-वे बनाने से बात नहीं बनेगी। हाईवे या एक्सप्रेस-वे बनाने के बाद नया टोल प्लाजा एनसीआर के ऊपर थोप दिया जाता है।

जल्द चालू होने वाला है जाम का नया प्वाइंट

कुछ महीने बाद एक नया टोल प्लाजा द्वारका एक्सप्रेस-वे पर बजघेड़ा बार्डर के नजदीक चालू होगा, यानी ट्रैफिक जाम का एक प्वाइंट जल्द ही चालू होने वाला है। एनसीआर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के 10 से अधिक टोल प्लाजा हैं। इनके अलावा दिल्ली में प्रवेश करने वाले लगभग सभी रास्तों पर दिल्ली नगर निगम के टोल प्लाजा हैं। लोक निर्माण विभाग के अपने टोल प्लाजा भी हैं। इनकी वजह से एनसीआर में विकास की रफ्तार गति नहीं पकड़ रही है। आखिर इन टोल प्लाजा से रोज कैसे जाम लग रहे हैं और किस तरह से विकास प्रभावित हो रहा, इसको लेकर प्रस्तुत है गुरुग्राम से आदित्य राज की रिपोर्ट: कारोबार को लेकर एक-दूसरे से जुड़े हैं एनसीआर के शहर

कारोबार के हिसाब से दिल्ली सहित एनसीआर के सभी शहर एक-दूसरे से जुड़े हैं। इस वजह से दिन में किसी-किसी दिन कई बार कारोबारियों को या उनके लोगों को आना-जाना पड़ता है।

माल ढुलाई करने वाले वाहन जितनी बार जाते हैं, उतनी बार टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल प्लाजा पर वाहनों का दवाब रहता है। इससे जहां माल ढुलाई में समय लगता है, वहीं ईंधन की खपत भी बढ़ती है।

आईटी, आइटी इनेबल्ड, टेलीकॉम, आटोमोबाइल एवं गारमेंट सेक्टर में पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाले गुरुगाम की तस्वीर आज और बेहतर होती यदि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर खेड़कीदौला टोल प्लाजा नहीं होता

टोल प्लाजा के चलते गुरुग्राम से आने-जाने वाले होते हैं परेशान

खेड़कीदौला टोल प्लाजा की वजह से गुरुग्राम शहर से मानेसर व मानेसर से गुरुग्राम शहर आने-जाने से पहले दस बार सोचना पड़ता है।

पीक आवर के दौरान ही नहीं, बाकी समय के दौरान भी वाहनों का दवाब टोल प्लाजा पर रहता है। इससे मानेसर का ही नहीं बल्कि, पूरे गुरुग्राम का विकास प्रभावित हो रहा है। सेक्टर-37, सेक्टर-34, सेक्टर-35 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास ठहर सा गया है।

इसी तरह गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर घामड़ोज टोल प्लाजा, दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर सोनीपत में टोल प्लाजा, दिल्ली-आगरा हाईवे पर बदरपुर टोल प्लाजा, दिल्ली-मेरठ हाईवे पर डासना बार्डर टोल प्लाजा सहित एनसीआर के अंतर्गत आने वाले सभी टोल प्लाजा की वजह से विकास की रफ्तार प्रभावित हो रही है। प्रतिदिन लाखों वाहन इन टोल प्लाजा से होकर गुजरते हैं।

इन टोल प्लाजा को खत्म करते ही हजारों करोड़ रुपये की होगी बचत

हरियाणा के पूर्व मुख्य नगर योजनाकार व पर्यावरण कार्यकर्ता प्रो. केके यादव कहते हैं कि टोल प्लाजा की वजह से टाइम, एनर्जी और मनी तीनों का भारी नुकसान हो रहा है। यह नुकसान हजारों करोड़ में होगा।

टोल प्लाजा को खत्म करते ही न केवल हजारों करोड़ की बचत होगी बल्कि, विकास की गति तेज होगी। एनसीआर में आने-जाने से पहले अधिकतर लोगों को सोचना पड़ता है। हर तरफ टोल प्लाजा है।

मानेसर के लोग गुरुग्राम बिना टोल दिए नहीं जा सकते। सोहना के लोग गुरुग्राम बिना टोल दिए नहीं आ सकते। गुरुग्राम के लोग फरीदाबाद बिना टोल दिए नहीं जा सकते। ऐसे में कैसे विकसित भारत और आकांक्षी एनसीआर का सपना साकार होगा।

एनसीआर देश के विकास का आईना है। जब तक आईना बेहतर नहीं होगा, तब तक कहीं भी विकास का कोई मतलब नहीं। सरकार पालिसी बनाकर सभी टोल प्लाजा को खत्म करे। भले ही वाहनों के पंजीकरण के समय ही रोड टैक्स सरकार वसूल ले।

टोल प्लाजा के मामलों में की जा रही नियमों की अनदेखी, उठी है इन्हें हटाने की मांग

नियमानुसार नगर निगम सीमा से 10 किमी के दायरे में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कहीं भी टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। पांच से 10 किमी के दायरे में टोल प्लाजा बहुत ही विशेष परिस्थिति में चालू किया जा सकता है। इसके लिए एनएचएआई के चेयरमैन से अनुमति लेनी आवश्यक होती है। इसका अधिकतर जगह उल्लंघन दिख रहा है। उदाहरणस्वरूप गुरुग्राम का खेड़कीदौला टोल प्लाजा नगर निगम क्षेत्र के दायरे में है।

स्थानीय सांसद व केंद्रीय योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह कई बार इस टोल प्लाजा को हटाने की मांग कर चुके हैं। एनसीआर के अधिकतर टोल प्लाजा नगर निगम की सीमा क्षेत्र से 10 किमी के दायरे में हैं। यदि इस नियम का भी ईमानदारी से पालन किया जाय तो अधिकतर टोल प्लाजा बंद हो जाएंगे।

बनानी पड़ेगी पॉलिसी

एनएचएआइ में लंबे समय तक परियोजना निदेशक रहे एके शर्मा का कहना है कि सभी परियोजनाएं पीपीपी माडल पर आधारित होती हैं। यानी पैसा कोई कंपनी लगाती है, जो कंपनी पैसा लगाएगी वह वसूली भी करेगी। टोल प्लाजा से लागत वसूली जाती है। ऐसे में टोल प्लाजा खत्म करने की केंद्र सरकार को नई पालिसी बनानी होगी।

दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बनी दिल्ली

आपका रिपोर्ट कार्ड: दिल्ली के दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनने के बाद केजरीवाल से एलजी

दुनिया की 'सबसे प्रदूषित राजधानियों' की सूची में दिल्ली के शीर्ष पर रहने के बाद दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, "आपकी सरकार के 9 साल का यह रिपोर्ट कार्ड ऐसा नहीं है जिसपर आपको गर्व हो।" उन्होंने कहा, "खराब वायु गुणवत्ता...स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों के लिए भी खतरनाक है।"

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सवाल यह नही की कसूर किसका है ? सवाल यह है कि आखिर कब तक इन हालातों में हम लोग मरते रहेंगे ? प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण है, सडकों पर बेहिसाब वाहन। बेहिसाब वाहनों मे सबसे बड़ा कारण हैसार्वजनिक सवारी सेवा वाहनों का जनता को उपलब्ध नही होना और जनता को एक कार से करनी पड़ती है अपनी जरुरत पूरी और एक कार में एक सवारी। मजबूर जनता को वाहन निर्माताओं के साथ मिलकर वाहन खरीदने के लिए मजबूर करना और जितनी चाहे कारें खरीदे कोई रोक नही है। घर हो चाहे साढ़े बारह गज का परन्तु कार खरीदने की जरुरत और कोई रोक नही। हर चौराहे पर खाने पीने की दूकाने ओर उन दूकानों पर खड़ी कारें। हर चौराहे पर बेहिसाब बैटरी रिक्शा।

आखिर कब तक और किसके कारण ? जिम्मेदार कोन ?

केजरीवाल को किया घर से गिरफ्तार

2 घंटे चली ईडी की पूछताछ....

परिवहन विशेष न्यूज

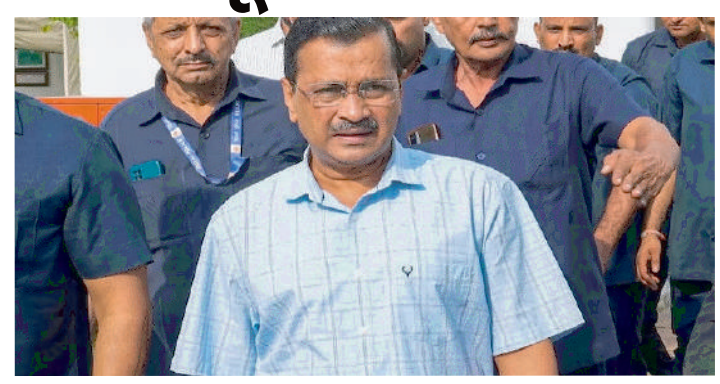

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया। लगातार 2 घंटा केजरीवाल से ईडी टीम ने पूछताछ की। विभागीय सूत्रों से पता चला है कि केजरीवाल उनके किसी जवाब का उत्तर ठीक ढंग से नहीं दे पाए। मामला, शराब नीति घोटाला से जुड़ा है। सूत्रों से पता चला है कि ईडी को इस केस में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल हुए। फिलहाल, इस बारे कोई किसी प्रकार से अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सारा इलाके की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। बताया जा रहा है कि मामला काफी गंभीर तथा राजनीति से जुड़ा है। किसी प्रकार के बवाल से पूर्व ही अत्याधुनिक तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर, आप के कई वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री के समर्थन में उतर आए है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक प्रकार से ईडी भाजपा के इशारे पर केजरीवाल के खिलाफ जुर्म कर रही है। लेकिन, भाजपा आप के आरोपों का खंडन करते हुए इसे ईडी की कार्रवाई बता रही है।

दरअसल, पिछले दिनों ईडी ने अदालत समक्ष कहा था कि अरविंद केजरीवाल उनके एक भी समन का जवाब नहीं दे रहे है। पता चला है कि केजरीवाल को शराब नीति घोटाला में लगभग ईडी ने 1 दर्जन के करीब समन भेज कर सवाल जवाब के उपस्थित होने के बुला था। लेकिन, उन्होंने हर बार समन को नजरअंदाज किया। आखिरकार , अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। पता चला है कि टीम ने देर शाम केजरीवाल के सरकारी आवास पहुंचे। उनसे 2 घंटा लगातार पूछताछ हुई। किसी भी उत्तर का जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने आसपास के इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है, ताकि गिरफ्तारी के दौरान किसी प्रकार से टीम के कार्य में कोई किसी प्रकार से विघ्न नहीं डले। सुबह केजरीवाल को ईडी अदालत में पेश कर सकती है। टीम इस बात की मांग कर सकती है कि उन्हें केजरीवाल की न्यायिक हिरासत हासिल हों। क्योंकि, कई सवाल शराब घोटाले के साथ संबंधित है, जिसका जवाब मिलना अभी शेष है। बता दें कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी कविता को गिरफ्तार किया था। फिलहाल, ईडी की कस्टडी में है। लगातार सवाल जवाब जारी है।

कानूनी टीम पहुंची सर्वोच्च न्यायालय

आप पार्टी के सूत्रों से पता चला है कि उनकी एक लीगल टीम सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। उनका इरादा है कि अपील कर केजरीवाल को जमानत ली जाए। लेकिन, कानून सलाहकार इस बात को लेकर सहमत नहीं है। उनका मानना है कि केजरीवाल को इस मामले में जमानत अदालत इतनी जल्द नहीं दी सकती है। क्योंकि, इस मामले के तार पूरे देश के कई हिस्सों से जुड़े है। अब तक कई बड़े राजनेता तथा कारोबारी जेल के भीतर है। किसी को जमानत नहीं मिली है। ईडी के पास मजबूत सबूत होने की वजह से अदालत अब तक किसी को जमानत नहीं दे पाई।

..ऐसे पता चला था घोटाला

दरअसल, दिल्ली के उपराज्यपाल ने सबसे पहले इस घोटाले के प्रति आवाज उठाई थी। उन्होंने मामले की जांच पूर्व पुलिस टीम को दी थी। टीम की स्पेशल टीम ने इस केस में बताया था कि तार काफी लंबे जुड़े है। मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा तो जांच ईडी को सौंपी गई। ईडी ने अपनी जांच पड़ताल में पाया कि शराब नीति में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। इसमें राजनीति से जुड़े लोगों ने देश के बड़े-बड़े शराब कारोबारियों को काफी फायदा पहुंचाया। नियमों की पूर्ण रुप से उल्लंघन हुई। सबसे अधिक आप पार्टी के बड़े नेता शामिल थे। कई नेता जेल की सलाखों के पीछे है। अब केजरीवाल भी उनका साथ निभाने के लिए जेल में पहुंच रहे है।

मान ने बोला''.सच्चाई नहीं होगी खत्म

भगवंत मान ने कहा कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता, कभी उसे खत्म भी नहीं किया जा सकता है। राजनीति शरण लेकर ईडी का दुरुपयोग किया गया। जानबूझकर आप के मुख्यमंत्री को फंसाया गया। जल्द वह जेल से बाहर आएंगे। दुनिया सब जानती है कि सच्चाई क्या है, जनता केजरीवाल तथा आप पार्टी के साथ है।

जेल से चलेगी सरकार

आप के शराब नीति घोटाले को लेकर कई मंत्री जेल में है। अब केजरीवाल को भी जेल भेज दिया गया। पता चला है कि अब जेल से दिल्ली के सरकार चलेंगी। कोशिश इस बात की भी हो रही है कि केजरीवाल को जमानत दिलाई जाए। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय लीगल टीम पहुंच गई। उनका पक्ष रखने के लिए लंबी बहस हो सकती है।

चुनौती योग्य नेता, आप के सर्वे की माने तो जेल से ही दिल्ली की सत्ता चलाएंगे केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (आप) के सामने अब चुनौती एक योग्य नेता को सामने लाने की है। जो उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली में पार्टी और सरकार दोनों को संभाल सके। पूर्व आईआरएस अधिकारी सुनीता केजरीवाल के अलावा आतिशी और सौरभ भारद्वाज की भी दावेदारी हो सकती है। आतिशी दिल्ली सरकार में शिक्षा, वित, पीडब्ल्यूडी, राजस्व और सेवाओं सहित सबसे अधिक विभाग हैं। केजरीवाल की करीबी भी माना जाता है। भाजपा पर हमला भी रही है। भारद्वाज दिल्ली मंत्रिमंडल के एक प्रमुख सदस्य हैं, जिनके पास स्वास्थ्य और शहरी विकास सहित कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। वह, भी, पार्टी का एक जाना-माना चेहरा हैं, जो अक्सर पार्टी और इसके नेताओं का बचाव करने और केंद्र में भाजपा और इसकी सरकार को राजनीतिक मुद्दों पर जवाबी हमला करने में लगे रहते हैं। आप नेता कुमार गौतम का कहना है कि पिछले साल दिसंबर में, आप ने एक हस्ताक्षर कैंपेन चलाया गया था। "मैं भी केजरीवाल" जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या गिरफ्तार होने पर जेल से सरकार चलानी चाहिए। अभियान के दौरान 90 प्रतिशत लोगों की राय थी कि केजरीवाल के पास ही दिल्ली का जनादेश है। चुने हुए मुख्यमंत्री है। वह जेल में रहे है या कही थी, मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने इस बाबत सर्वे भी कराया था तो उसमें भी यही बात निकल कर सामने आई थी कि जेल से ही सत्ता संभालेंगे अरविंद केजरीवाल।

दिल्ली परिवहन निगम को प्राइवेट करने एवं **दिल्ली परिवहन निगम को बर्बाद करने में शामिल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, बर्बादी की खुशी में डी टीसी कर्मचारी एकता यूनियन द्वारा कल** दिनांक 22-3-2024 को डी टीसी मुख्यालय पर सुबह 10 बजे ढोल बजाकर एवं मिठाई, बाटकर उनके जेल जाने की खुशी का जश्न मनाया जाएगा! यूनियन दिल्ली परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों को इस जश्न में आने का निमंत्रण देती है!

जिस व्यक्ति ने दिल्ली परिवहन निगम को बर्बाद करने की रंजिश के तहत दिल्ली परिवहन निगम को प्राइवेट स्टेशन की ओर धकेला है आज इसकी बर्बादी पर जिसने दिल्ली परिवहन को बर्बाद करने की कोशिश की इसकी बर्बादी के जश्न में डी टीसी **कर्मचारी एकता यूनियन तह दिल से अभिनंदन करेगी!**

निवेदक :- **डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन**
अध्यक्ष ललित चौधरी 9582180001
महामन्त्री मनोज शर्मा 9911905268

नजर रेलवे अधिकारियों के साथ ही रेलवे पुलिस की खासतौर से तैनाती की गई है। एंबुलेंस व डॉक्टरों की टीम की तैनाती भी रहेगी।

होली पर इस बार रेलवे की तैयारी: 100 से अधिक ट्रेन, स्टेशन के बाहर पंडाल; दलालों पर नजर, खुफिया टीम की तैनाती

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। होली त्योहार को लेकर उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रख रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। यात्रियों की तादाद को देखते हुए 100 से अधिक ट्रेन चलाई जा रही है, वहीं प्लेटफार्म पर भीड़ नियंत्रण के लिए स्टेशन परिसर में ही टेंट का इंतजाम किया गया है। जहां एलईडी स्क्रीन से ट्रेन संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। स्टेशनों पर मोबाइल शौचालय का इंतजाम किया गया है।

विशेष तौर पर किसी अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए डॉग स्क्वायड की टीम तो उतारी ही गई है साथ ही रेलवे पुलिस खुफिया की खुफिया इकाइयां केंद्रीय खुफिया विभाग के साथ नियमित संपर्क में हैं। आरक्षित कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों के पहचान पत्र की गहन जांच के लिए टीम उतारी गई है। खास बात यह भी है कि दिल्ली के सभी मुख्य स्टेशन पर एंबुलेंस की तैनाती के साथ डॉक्टरों की टीम की नियुक्ति की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए पुख्ता प्रबंध किया गया है।

पिछले साल यात्रियों की भीड़ स्टेशनों पर होली के दौरान उमड़ पड़ी थी। उस प्रवृति को आधार बनाकर रेलवे ने इस बार खास इंतजाम किया है। दिल्ली से राजगीर, पटना, ओखा, आरा, गया, वाराणसी, छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंबई सेंट्रल, जयनगर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, पुरी और राष्ट्रीय राजधानी से अन्य व्यस्त मार्ग के लिए 2 अप्रैल तक 100 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। सर्कुलेटिंग एरिया में भीड़ को रोकने के लिए अजमेरी गेट की तरफ 4500 वर्ग फीट का पंडाल तैयार किया गया है। इसी तरह आनंद विहार टर्मिनल 2500 वर्ग फीट का पंडाल बना है। रेलवे स्टेशनों एयरपोर्ट की तरह यात्री होल्डिंग एरिया का गठन किया गया है। प्लेटफार्मों पर भीड़ न उमड़े इसे ध्यान में रख प्रतीक्षा क्षेत्र, कवर टेंट, लाइटिंग, पंखे, वॉटर बूथ, पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक, फूड स्टॉल, अतिरिक्त बुकिंग काउंटर की सुविधा दी गई है।

यात्रियों को आनंद विहार टर्मिनल पर मिलने वाली सुविधा

-2500-3000 वर्ग फुट का पंडाल तैयार किया गया है।
-महिला और पुरुष यात्रियों के लिए मोबाइल शौचालय की सुविधा।
-पानी का टैंकर उपलब्ध कराया गया है।
-पांच अतिरिक्त पूछताछ व टिकट काउंटर उपलब्ध है ।
-जनता खाना सभी स्टाल पर उपलब्ध रहेगा।
-टेंट में एलईडी स्क्रीन लगाई गई है।
-यात्रियों को सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मिनी कंट्रोल रूप तैयार किया गया है।
-नई दिल्ली के अजमेरी गेट की तरफ 4500 वर्ग फुट का पंडाल तैयार किया गया है।
-महिला और पुरुष यात्रियों के लिए मोबाइल शौचालय की सुविधा
-पंडाल में 20 अतिरिक्त पानी के नल लगाए गए है।
-खान-पान के लिए दो अतिरिक्त स्टॉल लगाया गया है।
-यात्रियों की सुविधा के लिए मिनी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है।
-पहाड़ गंज और अजमेरी गेट की तरफ मे आई हेल्प यू काउंटर लगा है।

दलालों व असामाजिक तत्वों पर रहेगी

नजर रेलवे अधिकारियों के साथ ही रेलवे पुलिस की खासतौर से तैनाती की गई है। साफ-सफाई के साथ ही स्काउट और गाइड, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करेंगे। प्लेटफार्म और फुटओवर ब्रिज पर यात्रियों की भीड़ का प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे पुलिस, सिविल पुलिस में समन्वय बैठाया गया है। महत्वपूर्ण यात्री ट्रेनों को एस्कॉर्ट किया जा रहा है। खोजी कुत्तों के साथ तोड़-फोड़ रोधी जांच और जीआरपी व सिविल पुलिस के साथ संयुक्त निगरानी की जा रही है।

एंबुलेंस व डॉक्टरों की टीम की तैनाती

हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और पानीपत रेलवे स्टेशनों पर एंबुलेंस तैनात की गई है। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पर्याप्त संख्या में काम करने योग्य स्थिति में व्हील चेयर उपलब्ध हों सके। इसी तरह स्टेशन पर डॉक्टर की टीम को 25 मार्च तक के लिए तैनात किया गया है। सभी मुख्य स्टेशन पर ड्यूटी अधिकारी तैनात रहेंगे।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिनभर खुश और स्ट्रेस फ्री रखेंगी आपकी 5 अच्छी आदतें, वर्किंग वूमेन जरूर करें फॉलो, हमेशा रहेंगी फिट और हेल्दी

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलती जीवनशैली में अधिकतर लोग मेंटली कमजोर होते जा रहे हैं. मेंटल स्ट्रेस बढ़ने का एक बड़ा कारण फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी देखी जा रही है. दरअसल, वर्तमान में ज्यादातर काम कंप्यूटर या डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं, जिससे फिजिकल एक्टिविटी न के बराबर रह गई है. ऐसे में खुश और स्ट्रेस फ्री रहना मनो असंभव सा लगता है. घर और ऑफिस दोनों जगहों के काम का भार महिलाओं पर अधिक पड़ता है. इससे महिलाओं में तनाव के मामले अधिक देखे जाते हैं. यदि आप भी ऐसा ही महसूस करती हैं तो कुछ आसान टिप्स आपना कर दिनभर स्ट्रेस फ्री और खुश रह सकती हैं. आइए जानते इन आदतों के बारे में-

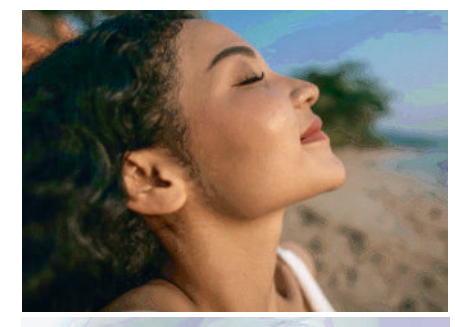

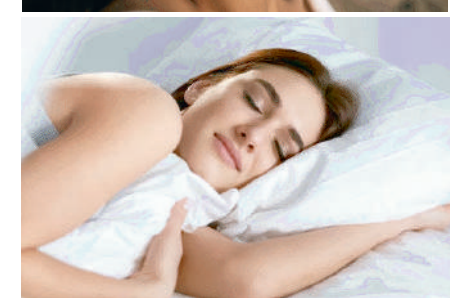

मुस्कुराते रहें: हेल्थलाइन के मुताबिक अधिकतर लोगों को लगता है कि उन्हें स्माइल तब करनी चाहिए जब वे खुश होते हैं लेकिन स्माइल खुश होने के लिए भी की जा सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार खुश रहने के लिए भी स्माइल करना जरूरी है क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन डोपामाइन रिलीज करता है. इसलिए दिन भर खुश और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अपनी सुबह की शुरुआत एक मुस्कुराहट से करनी चाहिए.

एक्सरसाइज: सेहतमंद रहने के लिए हर दिन की शुरुआत एक्सरसाइज या योग से करनी चाहिए. ऐसा करने से आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं और डिप्रेशन के लक्षणों से बचे रहते हैं. आप अपने दिन की शुरुआत किसी भी फन एक्टिविटी के साथ कर सकती हैं ऐसा करने से आप दिनभर एक्टिव और स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगी.

अच्छी नींद: सेहतमंद रहने के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है. आजकल के बिजी शेड्यूल में नींद का प्रभावित होना एक आम समस्या है, जिसके कारण आप दिनभर मेंटली और फिजिकली थका हुआ महसूस करती हैं. रात में अच्छी नींद लेने से आप हेल्दी रहने के साथ-साथ पूरे दिन खुश और स्ट्रेस फ्री रह सकती हैं. (Image- Canva)

दिन को प्लान करें: आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अपने साथ एक डायरी या जर्नल रखने की आदत डालनी चाहिए. दिन की सही प्लानिंग करने से आपको इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगी. हमेशा खुश और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अपनी डायरी में अच्छी यादों को संजोए और बुरी यादों को लिखकर भूल जाएं.

गहरी सांस लें: दिनभर की भागदौड़ में स्ट्रेस फ्री और खुश रहने के लिए आप छोटे-छोटे ब्रेक में आंखें बंद कर लंबी गहरी सांस प्रैक्टिस कर सकती हैं, ऐसा करने से आप तुरंत रिलैक्स महसूस करेंगी और दिनभर खुश और स्ट्रेस फ्री रहेंगी.

बच्चे के जन्म के समय से ही होती है यह बीमारी, कहीं आपका बच्चा भी तो शिकार नहीं है इस डिसऑर्डर का

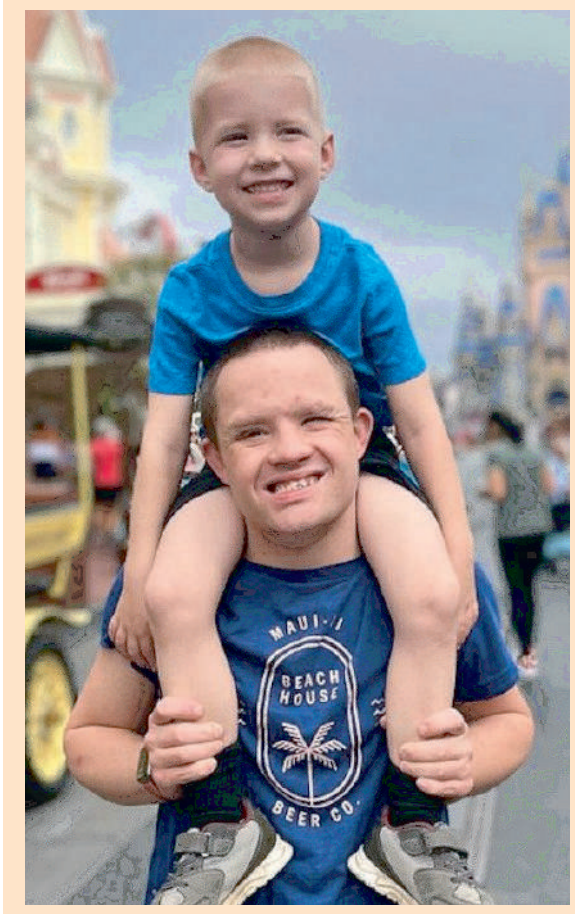

इंटरनेशनल डाउन सिंड्रोम सोसायटी (एनडीएसएस) के अनुसार, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी 700 बच्चों में से 1 बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है। इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। इसमें बच्चा मानसिक और शारीरिक विकारों से जूझता है। डाउन सिंड्रोम में बच्चा अपने 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है। इसे ट्राइसॉमी-2 भी कहा जाता है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर (आनुवंशिक विकार) होता है। इससे बच्चे के शारीरिक विकास में देरी, चेहरे की विशेषताओं में फर्क और बौद्धिक विकास में देरी होती है। यह डिसऑर्डर बच्चे के साथ जीवन भर तक रहता है। अब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि इस डिसऑर्डर का पता मां के गर्भ में ही लगाया जा सकता है। आइए जानते है इस बीमारी के बारे में डिटेल्स में कैसे होता है डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर रिप्रोडक्शन (प्रजनन) के समय माता के (xx) और पिता के (xy) दोनों के क्रोमोसोम बच्चे में जाते हैं। इनमें से कुल 46 क्रोमोसोम में से 23 माता के और 23 पिता से बच्चे को मिलता है।जब माता-पिता दोनों के क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो उनमें से 21वें क्रोमोसोम का डिविजन नहीं हो पाता है। जिस कारण 21वां क्रोमोसोम अपनी एक्स्ट्रा कॉपी बना देता है।यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बच्चे में कई तरह के शारीरिक और मानसिक विकार करता है। डाउन सिंड्रोम के लक्षण इसके लक्षण आपको बच्चे में जन्म से ही देखने को मिलेंगे। जैसे :-सपाट चेहरा, छोटा सिर और कान, छोटी गर्दन होने का पैदाइशी डिसऑर्डर, उभरी हुई जीभ, आंखें जो ऊपर की ओर झुकी हों और असामान्य आकार के कान। आपको बताते चलें कि हर साल मार्च के 21वें दिन (वर्ष के तीसरे महीने) में डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। जानकारी की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2012 से इसे प्रत्येक वर्ष मनाने का निर्णय लिया था। तब से यह डे हर साल मनाया जा रहा है

गाजियाबाद में 15 वर्ष में 65 प्रतिशत महिला मतदाता बढ़ीं, पुरुषों को छोड़ा पीछे

Lok Sabha Election 2024 वर्ष 2009 में हापुड़ के परिसीमन से गाजियाबाद सीट बनने के बाद से अब तक 15 वर्ष में महिला मतदाताओं में 65.76 की बढोतरी हुई है। वहीं पुरुष मतदाताओं में 56.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लोकसभा चुनाव-2024 में 29 लाख 38845 कुल मतदाता हैं। इनमें से पुरुष मतदाता 1622869 हैं और महिला मतदाता 1315872 हैं।

गाजियाबाद। महिलाएं अपनी सरकार चुनने के लिए पुरुषों से ज्यादा जागरूक हैं। यही कारण है कि बीते तीन लोकसभा चुनावों में महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले अधिक बढ़ा है। वर्ष 2009 में हापुड़ के परिसीमन से गाजियाबाद सीट बनने के बाद से अब तक 15 वर्ष में महिला मतदाताओं में 65.76 की बढोतरी हुई है। वहीं, पुरुष मतदाताओं में 56.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पुरुषों मतदाताओं के बढ़ने का क्रम महिलाओं के सापेक्ष नौ प्रतिशत कम है।

दरअसल, हापुड़ लोकसभा सीट से अलग होने के दौरान गाजियाबाद सीट पर कुल मतदाता 18 लाख 31,638 थे। इनमें से 10,37,889 पुरुष व 7,93,799 महिला मतदाता थीं। लोकसभा चुनाव-2024 में 29 लाख 38845 कुल मतदाता हैं। इनमें से पुरुष मतदाता 16,22,869 हैं और महिला मतदाता 13,15,872 हैं। महिलाओं का प्रतिशत हर लोकसभा चुनाव में पुरुषों के सापेक्ष अधिक बढ़ा है।

महिला मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा

लोकसभा चुनाव 2009 के बाद से महिलाओं को मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। 2009 में 41.83 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया था। अगले लोकसभा चुनाव 2014 में 54.68 प्रतिशत व 2019 में 55.11 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया। जबकि पुरुष मतदान 2014 में 58.68 व 2019 में घटकर 56.31 प्रतिशत रह गया।

2009 के सापेक्ष महिला मतदाता बढ़े

वर्ष	प्रतिशत
2014	29.06
2019	52.27
2024	65.76

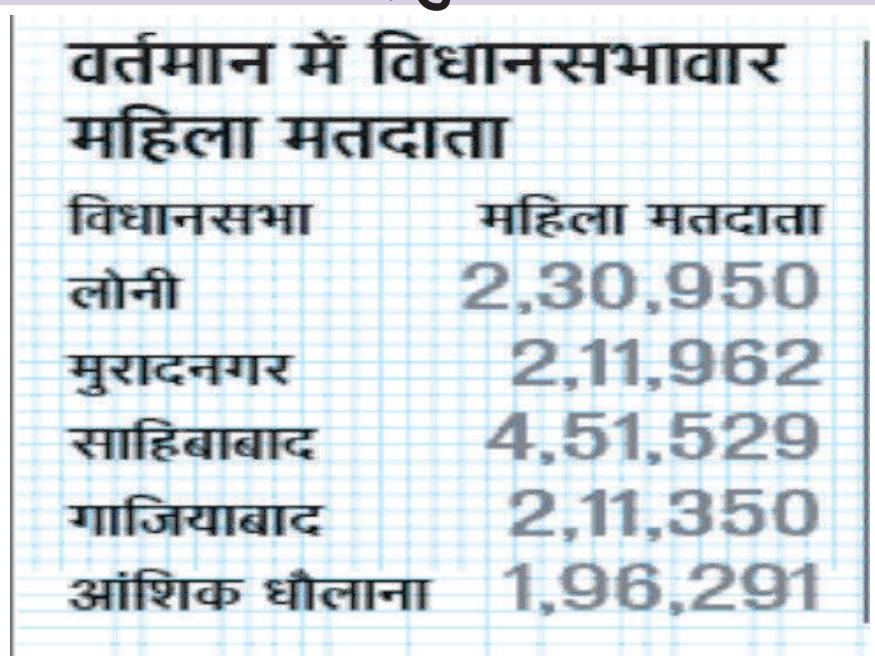

वर्तमान में विधानसभावार महिला मतदाता

विधानसभा	महिला मतदाता
लोनी	2,30,950
मुरादनगर	2,11,962
साहिबाबाद	4,51,529
गाजियाबाद	2,11,350
आंशिक धौलाना	1,96,291

सरकार बनाने में महिला मतदाताओं की होगी अहम भूमिका

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

सबसे अच्छी बात यह है कि गॉव हो या शहर महिलाएं अब घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली या पुरुष के कहे अनुसार मतदान करने वाली नहीं रही है। पुरुषों के हां में हां मिलाने वाली स्थिति से बहुत बाहर आ चुकी है आज देश की महिलाएं।

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में 18 वीं लोकसभा के चुनाव का विगुल बज गया है। मुख्य चुनव आयुक्त राजीव कुमार ने 18 वीं लोकसभा के लिए सात चरणों में मतदान का कार्यक्रम जारी कर दिया हैं वहीं 4 जून को मतगणना की तारीख तय की गई है। सीधी सी बात है कि 4 जून को दोपहर बाद तक 18 वीं लोकसभा की तस्वीर साफ हो जाएगी। खैर यह सब अलग बात है पर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनावों में महिलाओं की बढ़ती सक्रिय भागीदारी तारीफे काबिल है। गत दो चुनावों ने देश की महिला वोटरों ने नई सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मजे की बात यह भी है कि 2019 के चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं ने अधिक मुखर होकर मतदान किया है। अब तो यह माना जाने लगा है कि देश के एक दर्जन के करीब राज्यों में महिलाओं के वोट ही नई सरकार के गठन में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तस्वीर का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि मतदान ही नहीं चुनावों में सक्रियता से हिस्सा लेने और चुनावों में उम्मीद्वारी जताने में भी महिलाएं आगे आई हैं। देश के पहले और दूसरे लोकसभा के आमचुनावों में जहां 22 महिला सांसद चुन कर आई थी वहीं गत 2019 के आमचुनाव में 78 महिला सांसद चुन कर आई। हांलाकि आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नए नए सब्जबाग दिखाने के बावजूद टिकट वितरण के समय महिलाओं की हिस्सेदारी कम ही रह जाती है। अनुभव तो यही बताता है कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा आधी तो दूर की बात एक तिहाई सीटों पर भी महिलाओं को टिकट नहीं दिए जाते है।

खैर सबसे अच्छी बात यह है कि गॉव हो या शहर महिलाएं अब घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली या पुरुष के कहे अनुसार मतदान करने वाली नहीं रही है। पुरुषों के हां में हां मिलाने वाली स्थिति से बहुत बाहर आ चुकी है आज देश की महिलाएं। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में महिलाएं सक्रियता से हिस्सा लेने लगी हैं। चुनावों में उम्मीद्वारी भी जताती है तो चुनाव केंपेन के दौरान अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराती है। दूसरी और मतदान में आगे आकर हिस्सा लेने लगी है। पिछले चुनावों के आंकड़ों से यह सब साफ हो चुका है। इस साल देश में 96 करोड़ 88 लाख मतदाता है तो इनमें से महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ 15 लाख के करीब है। एक मोटे अनुमान के अनुसार पुरुषों की तुलना में करीब दो करोड़ महिला मतदाता कम है। कमोबेस यही स्थिति 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान थी। इस सबके बावजूद पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं के मतदान का आंकड़ा अधिक है। 2019 के चुनावों में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 67.02 प्रतिशत रहा तो महिलाओं के मतदान का प्रतिशत 67.18 प्रतिशत रहा। पूर्वोत्तर, हिमाचल, गोवा, बिहार सहित बहुत से प्रदेशों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा। यह तो रही मतदान की बात तो दूसरी और नई सरकार बनाने में भी महिला मतदाताओं की अधिक भूमिका रही है। देखा जाए तो महिलाओं ने जिस दल पर अधिक भरोसा जताया या यों कहे कि जिस दल को अधिक मत दिए उसी दल की सरकार बनी। मजे की बात यह है कि 2014 में मोदी सरकार बनने और 2019 में रीपिट होने का प्रमुख कारण भी महिलाओं को भाजपा और खासतौर से नरेन्द्र मोदी पर अधिक भरोसा जताने को जाता है। 2004 के चुनावों में 22 प्रतिशत महिलाओं ने भाजपा और 26 प्रतिशत पुरुषों ने कांग्रेस को वोट दिया था वहीं 2019 के चुनाव आते आते इसमें जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। 2019 के चुनावों में महिलाओं द्वारा मोदी में विश्वास व्यक्त करने का आंकड़ा 36 प्रतिशत पहुंच गया। यानी कि 2019 के चुनावों में 36 फीसदी महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया। महिलाओं के अधिक मतदान का ही परिणाम रहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा और नरेन्द्र मोदी को जबरदस्त मेजोरिटी प्राप्त हुई।

विगत दो लोकसभा चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए अब सभी राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के हर संभव प्रयास में जुट गए हैं। यही कारण है कि महिलाओं को लुभाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम ना केवल घोषित किये जा रहे हैं अपितु राजनीतिक दलों के आने वाले चुनाव घोषणा पत्रों में महिला मतदाताओं को लुभाने के हर संभव प्रयास होंगे। क्योंकि एक बात साफ हो चुकी है कि आज की महिला स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है और उसको दबाव या अन्य तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता। कम से कम विगत चुनावों के परिणाम तो इसी और इंगित कर रहे हैं। खास तौर से आने वाले दिनों में चुनाव केंपेन महिला केंद्रीत हो तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता। देश की विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं के चुनावों में हम यह साफ रुप से देख चुके हैं। केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना, मध्यप्रदेश की लाडली योजना, लखपति लाड़ली योजना, महिला मुखिया को नकद राशि और मुफ्त बस यात्रा ने कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में देखा जा चुका है। आप महिला सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। लगभग सभी राजनीतिक दल इस दिशा में आगे आ रहे हैं और आने वाले दिनों में यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा।

खैर यह अलग बात है, पर यह साफ हो चुका है कि देश के लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाने जा रही है। अब महिला मतदाताओं को कमतर नहीं आंका जा सकता। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसे शुभ संकेत माना जा सकता है। पर अब यह साफ हो जाना चाहिए कि चुनावों के दौरान आने वाले दिनों में महिलाओं की और सभी राजनीतिक दलों की नजर रहेगी और महिलाओं को मतदान के लिए अपने पक्ष में करने के हर संभव प्रयास होंगे। इसे देश और लोकतंत्र दोनों के लिए ही सकारात्मक प्रयास कहा जा सकता है तो दूसरी और दुनिया के देशों के लिए भी भारत की महिलाएं एक मिसाल बन कर सामने आ रही हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि आने वाले चुनावों में राजनीतिक दलों की निगाहें महिला मतदाताओं की और ही रहेगी।

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भाजपा ने दी प्रतिक्रिया, जानें किसने क्या कहा

परिवहन विशेष न्यूज

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में बहाने बना रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नाटकबाजी वो कर रहे थे उसका आज अंत हो गया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र नहीं देंगे। आप नेताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है तो वहीं गिरफ्तारी को लेकर भाजपा और कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने टिप्पणी की है। जानें किसने क्या कहा..

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में बहाने बना रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नाटकबाजी वो कर रहे थे उसका आज अंत हो गया है। आज आखिरकार सत्य की जीत हुई है और मुझे विश्वास है।' पूरे युवाओं को शराब की लत में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम यही होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी।

उदित राज का ईडी की कार्रवाई पर बड़ा तंज

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर को सुरक्षा बलों ने ऐसे घेर लिया है जैसे वे किसी डाकू को पकड़ने आए हों या किसी दुश्मन देश से युद्ध चल रहा हो। यह लोकतंत्र की हत्या है। आगे कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल अपना गठबंधन खत्म करते हैं और बीजेपी के साथ गए, तो सभी समन वापस ले लिए जाएंगे। अगर अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया गया, तो सिर्फ आप या कांग्रेस को ही नहीं, सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

ईडी की कार्रवाई पर जेएमएम नेता महुआ माजी भी भड़कीं

ईडी की कार्रवाई पर राज्यसभा सांसद और जेएमएम नेता महुआ माजी ने कहा कि जहां-जहां गैर-भाजपा सरकार है, उन राज्यों

में ही ये चीजें हो रही हैं। चुनाव होने वाले हैं। आदर्श आचार संहिता लागू है। लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं। पहले झारखंड और फिर दिल्ली में ये लोकतंत्र नहीं बल्कि निरंकुशता की तैयारी है।

तृणमूल कांग्रेस केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करती है: डेरेक

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा में पार्टी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी की कारवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की गिरफ़्तारी की कड़ी निंदा करते हैं, खासकर तब जब चुनाव आयोग प्रभारी है और देश में चुनाव आचार संहिता (एमसीसी) लागू है।

डेरेक ने एक्स पर लिखा- इससे पहले एक अवैध अध्यादेश के ज़रिए उनकी (दिल्ली सरकार) प्रशासनिक शक्तियां छीन ली गई थीं। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री और प्रमुख विपक्षी नेताओं को चुनाव से पहले गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो हम भारत में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तृणमूल नेता ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग अभी कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो भविष्य में भाजपा की दमनकारी राजनीति के ख़िलाफ़ लोगों के साथ कौन खड़ा होगा?

अखिलेश यादव का बयान- भाजपा अब सत्ता में नहीं आने वाली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि जो ख़ुद हैं शिकस्त के ख़ौफ़ में क़ैद 'वो' क्या करेंगे किसी और को क़ैद, भाजपा जानती है कि वो फिर दुबारा सत्ता में नहीं आनेवाली, इसी डर से वो चुनाव के समय, विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है, गिरफ़्तारी तो बस बहाना है। ये गिरफ्तारी एक नयी जन-क्रांति को जन्म देगी।

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने की टिप्पणी

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि शराब नीति मामले में कुछ दिन पहले बीआरएस नेता के कविता को भी गिरफ्तार किया। यह एक बड़ी गिरफ्तारी का संकेत था कि आने वाले दिनों में इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। यह स्वाभाविक था कि इस मामले की आखिरी कड़ी अरविंद केजरीवाल तक पहुंचनी थी। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया भी गिरफ्तार हैं। उनकी गिरफ्तारी बस कुछ ही समय की बात थी।

अन्नाद्रमुक के प्रवक्ता ने गिरफ्तारी को बताया भाजपा का तीन सूत्री एजेंडा

सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्नाद्रमुक के प्रवक्ता कोवई सत्यन ने कहा कि यह गिरफ्तारी साबित करती है कि भाजपा के लिए तीन सूत्री एजेंडा है। पहला, जो भी भाजपा का विरोध करेगा, उसे सलाखों के पीछे से चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरा, जो भी भाजपा का विरोध करेगा, उसके पास धन और पैसा खत्म हो जाएगा। पार्टी फंड का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। तीसरा, जो भी जमानत पर बाहर हैं, बीजेपी को उनके साथ गठबंधन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।

समाज सेवी सँस्थायें युवाओं के भविष्य को लेकर हुई सजग

संजय बाटला

नई दिल्ली, 20 मार्च 2024 को वाई बी ड़ी एस युथ बेस डवलपमेंट सोसाइटी रजिस्टर्ड दिल्ली (NGO) ने युवाओं को जागरूक करने व आत्मनिर्भर बनाने के लिये ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों व ब्लॉक अधिकारियों के साथ बैठक की । बैठक में प्रेजिडेंट श्री योगेश कुमार जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती मोनिका जी, उपस्थित रही।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये। 01, ऑर्गेनाइजेशन की ओर से अधिकारी अपने अपने एरिया में युवाओं को जोड़ेंगे। 02, जिन युवाओं में प्रतिभा है उसका ब्यौरा तैयार करके ऑर्गेनाइजेशन में जमा करेंगे। 03, महिलाओं को स्वयं हैल्प गुरुप के लिये प्रोत्साहित करेंगे। 04, ऑर्गेनाइजेशन को मजबुत बनाने के लिये फण्ड रेंज करने में सहायता करेंगे। 05, महिला/ पुरुषों युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिये खेलों का आयोजन करेंगे। 06, महिलाओं की सुरक्षा के लिये महिलाओं को जीवन रक्षक प्रशिक्षण दिलाने के लिये कार्य करेंगे। योगेश कुमार प्रेजिडेंट: 9818724806

"पंथक शिक्षा और जत्थेदार संतोख सिंह" विषय पर हुई विचार गोष्ठी

वक्ताओं ने पंथक मुद्दों के प्रति जत्थेदार संतोख सिंह की भूमिका पर की चर्चा

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। दिल्ली में पंथक शिक्षा संस्थानों के संस्थापक जत्थेदार संतोख सिंह की 96वीं जयंती के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ₹पंथक शिक्षा और जत्थेदार संतोख सिंह₹ विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार चर्चा के दौरान सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, बैंकिंग और राजनीतिक क्षेत्र के विद्वानों ने पंथक मुद्दों के प्रति जत्थेदार संतोख सिंह की भूमिका के बारे में गंभीरता से अपनी राय व्यक्त की। वक्ताओं में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के पूर्व कुलपति डॉ. जसपाल सिंह, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना, इलाहाबाद बैंक के पूर्व अध्यक्ष हरभजन सिंह, गुरू नानक देव खालसा कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. हरमीत सिंह एवं दिल्ली कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह बाठ शामिल थे। दिल्ली कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने संगतों का धन्यवाद किया। एक पुलिस अधिकारी के रूप में लालपुरा ने 20 सितंबर 1981 को चौक मेहता में संत जरनैल सिंह भिंडरावाले की गिरफ्तारी के अवसर पर 50 हजार लोगों की सभा में जत्थेदार संतोख सिंह द्वारा उनकी मौजूदगी में दिए गए भाषण को याद करते हुए कहा कि जत्थेदार संतोख सिंह एक अच्छे राजनेता के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के बड़े नेता भी थे। उनके पास प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाकर उनसे बात करने की ताकत थी। यदि जत्थेदार संतोख सिंह अधिक समय तक जीवित रहते तो हम ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं देखना पड़ता। क्योंकि भिंडरावाले और इंदिरा गांधी दोनों ही जत्थेदार संतोख सिंह की बात मानते थे। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि 40 साल बाद भी हम जत्थेदार संतोख सिंह जैसा नेता पैदा नहीं कर सके। हालाँकि जत्थेदार संतोख सिंह के पास किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन उनमें आत्मिक ऊर्जा थी।

डॉ. जसपाल सिंह ने जत्थेदार संतोख सिंह के साथ बिताए गए समय को याद करते हुए कहा कि जत्थेदार संतोख सिंह ने अमीर विरासत को संरक्षित करने और विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए खुले दिल से काम किया था। उनके प्रमुख कार्यों में गुरू तेग बहादर साहिब की कैद की निशानी कोतवाली कौम को दिलवाना, महरौली में कुतुब मीनार के पास डॉक्टर गंडा सिंह से बाबा बंदा सिंह बहादर के शहीदी स्थल का सत्यापन करवाकर गुरुद्वारा साहिब की स्थापना करवाना और गुरू हरिक्रिशन पब्लिक स्कूलों तथा खालसा कॉलेजों की स्थापना करवाना शामिल था। इसके साथ ही जत्थेदार संतोख सिंह ने अपनी समृद्ध विरासत पर हमले से सचेत रहते हुए पंथक शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना आवश्यक समझा था। डॉ. जसपाल सिंह ने कहा कि जत्थेदार संतोख सिंह की एक बड़ी खूबी थी कि वे धर्म और विरासत पर खतरा देखते ही राजनीति से दूर होकर धर्म के साथ खड़े हो जाते थे। सरना ने एक दबंग आदमी के तौर पर जत्थेदार संतोख सिंह की खूबियों का जिक्र किया। सरना ने कहा कि जत्थेदार संतोख सिंह बुद्धिमान और सम्मानित सिखों को हमेशा अपने साथ रखते थे। यही कारण है कि गुरु हरिक्रिशन पब्लिक स्कूलों का उनके द्वारा लगाया गया पौधा अब पेड़ बन चुका है। लेकिन वर्तमान दिल्ली कमेटी प्रबंधकों की अक्षमता के कारण यह पेड़ अब ढहने की कगार पर है। सबसे अमीर कमेटी अब 700 करोड़ रुपये के कर्ज तले दबी हुई है। सरना ने सिखों के दुश्मन मीर मन्नू और जकरिया खान की रूह दिल्ली कमेटी के मौजूदा प्रबंधकों में आने का दावा करते हुए संगतों को इनका सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया।

हरभजन सिंह ने कहा कि जत्थेदार संतोख सिंह ने लड़कियों के लिए माता सुंदरी कॉलेज की स्थापना करके सिख परिवारों के लिए प्रगति का रास्ता खोला था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक लड़का उच्च शिक्षा प्राप्त करके केवल अपना ही फायदा करता है, लेकिन एक लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त करके पूरे परिवार की प्रगति का रास्ता खोलती है। बाठ ने दिल्ली कमेटी और खालसा स्कूलों के प्रबंध में अनियमितताओं के लिए कमेटी सदस्यों के साथ संगत को भी दोषी ठहराया, जो प्रलोभनों के तहत सदस्यों को चुनती हैं।

रामायण से जुड़ी जगहों के लिए आईआरसीटीसी लाया स्पेशल श्रीलंका टूर पैकेज...

नई दिल्ली:- अयोध्या की श्रीराम जन्म भूमि में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से ही लोगों के बीच रामायण से जुड़ी जगहों में घूमने का क्रेज बढ़ गया है. और अगर आप इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप भी आईआरसीटीसी दिल्ली से श्रीलंका के लिए स्पेशल 'श्री रामायण यात्रा' पैकेज लेकर इन सभी स्थानों के दर्शन कर सकते है. इस पैकेज का नाम है श्री रामायण यात्रा पैकेज रखा गया है. इस पैकेज में आपको दिल्ली से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जाने और आने के लिए फ्लाइट की सुविधा मिलेगी. कोलंबो, कैंडी और न्यूआरा ऐलिया की सैर का मौका मिलेगा. यह पैकेज 6 दिन और 5 रात का है. इस पैकेज में आपको कोलंबो के मुनेश्वरम मंदिर, मनावरी राम मंदिर, कैंडी के स्पाइस गार्डन, टी गार्डन, न्यूआरा एलिया के सीता अम्मा मंदिर, अशोक वाटिका आदि कई जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा. इस पैकेज में आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों की सुविधा के साथ ही होटल में ठहरने और मील की सुविधा दी जा रही है. पैकेज का शुल्क आपकी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से रखा गया है. सिंगल ऑक्यूपेंसी में 79,000 रुपये, दो लोगों की ऑक्यूपेंसी पर 65,000 रुपये और तीन लोगों की ऑक्यूपेंसी पर 64,000 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च आएगा.

फिल्म इंडस्ट्री में नये टैलेंट को प्रमोट करने के लिए गायक लोकेश गर्ग ने अपना प्रोडक्शन हाउस डे एंड डेज शुरू किया

नई दिल्ली। लोकेश गर्ग, प्रसिद्ध भारतीय गायक, संगीतकार, अभिनेता, और संगीत निर्माता, ने अपने प्रोडक्शन हाउस, डे एन डेज फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट की शुरुआत करके मनोरंजन उद्योग में कदम रखा है। गर्ग का ये नया कदम इंडस्ट्री में आने वाले नए लोगो को उनकी प्रतिभा के अनुसार अलग अलग अलग मौके देगा। दस साल के व्यापक करियर के दौरान, लोकेश गर्ग ने अपने आप को एक अच्छे कलाकार के रूप में स्थापित किया है, उन्होंने धार्मिक संगीत, पॉप हिट्स, और अभिनय भूमिकाओं से लोगो का दिल भी जीता है।

उनका संगीत और मनोरंजन के प्रति समर्पण ने उन्हें T-Series और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अच्छी फैन फॉलोइंग हासिल की है, जहां उनके काम ने करोड़ों दर्शकों को आकर्षित किया है। उनके करियर के दौरान, गर्ग ने 'तू ही वजूद', 'पीते पीते', और 'रुक रुक' जैसे पॉप गानों के साथ-साथ 'ये माँ होती है' और 'तेरी सूरत ने सांवरिया' जैसे धार्मिक हिट्स दिए हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी प्राप्तियां ने उनको भारत के सबसे सबसे प्रतिभाशाली और सफल गायको के रूप में स्थापित किया है। लोकेश गर्ग, जिनका जन्म 1 जुलाई, 1980 को हुआ था की पहचान एक बहुमुखी प्रतिभा के रूप में है जिन्होंने 2011 में धार्मिक संगीत से अपने करियर शुरू की थी।

मंडी हाउस- भारत की संस्कृति का केंद्र, जानें क्या है इसका इतिहास

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंडी हाउस का नाम तो आपने काफी बार सुना होगा। आप यहां आए भी होंगे या यहां से गुजरे भी होंगे। यह भारतीय सभ्यता व ललित कलाओं का केंद्र है। यहां आपको साहित्य अकादमी, संगीत-नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी से लेकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) तक का मुख्यालय मिल जाएगा।यह जगह कलाकारों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। जानकार बताते हैं कि 70 के दशक में यह कलाकारों का हब बन गया था। बात करें इस जगह के इतिहास की। यहां 1940 तक मंडी हाउस के 18वें राजा रहा करते थे। कलाकारों का हब बनने के पहले से यहां राज परिवार का राज चलता था। वक्त के साथ साथ राज परिवार का राज खत्म हो गया। बाद में राजा के महल की जगह हिमाचल भवन और दूरदर्शन की नींव रखी गई थी। आपको बता दें कि राजा का नाम सर जोगिंदर सेन बहादुर था। इनके महल के साथ ही बेहद खूबसूरत बगीचे का जिक्र भी किया जाता है।

अगर मंडी हाउस के आप पुराने नक्शों को देखें तो आपको जे सर्कल का जिक्र मिलेगा, जिसे जयसिंहपुरा गांव के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली बदली थी। तब जयसिंहपुरा गांव के आस-पास के कई भूखंडों को शाही रियासतों में आवंटित किया था। जिनमें बहावलपुर, नाभा, जींद, मलेरकोटला और मंडी का नाम आता है। आपको बता दें कि राजा जोगिंदर सेन बहादुर ने अपने महल के निर्माण

की शुरूआत साल 1930 में की थी, जिसे मंडी हाऊस कहा जाता था। वर्तमान में जहां हिमाचल भवन है वो ठीक उसके नजदीक हुआ करता था। इतिहासकार बताते हैं कि यहां दो मंजिला महल था जिस पर एक छोटा सा गुबंद भी हुआ करता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंडी हाउस का नाम भी राजा के महल के नाम पर रखा गया है।

आज़ादी के बाद साल 1955 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मंडी हाऊस सर्किल के दूसरी तरफ बाराखंभा रोड पर सप्रू हाऊस का उद्घाटन किया था। उनको शायद यह तब पता भी नहीं था कि आगे जाकर यह सांस्कृतिक प्रदर्शनों का केंद्र बन जाएगा। हैरानी की बात यह है कि आपको यहां कोई राजमहल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नाटक में बने राजाओं को आप देख सकते हैं। मंडी हाउस ने अपने अंदर आधुनिक और परम्परा को समेट कर रखा हुआ है। यहां पर स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) बेहद ही फेमस है। जहां कई छोटे छोटे शहरों से लोग अपने कलाकार बनने के सपनों को लेकर आते है। मंडी हाउस केवल राजधानी में स्थित जगहा ही नहीं बल्कि भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जो की कई लोगों के कलाकार बनने के सपनों को भी साकार करता है।

फ़ैक्टरियों और वाहनों से बढ़ रहा प्रदूषण, आईक्यू एयर रिर्पोट में टॉप-50 में शामिल है फ़रीदाबाद

परिवहन विशेष न्यूज

हाल ही में जारी की गई आईक्यू एयर रिपोर्ट में अनेक शहरों के प्रदूषण के हालत बयां हुए है। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा जा सकता है कि कैसे प्रदूषण कम करने के लिए जिला प्रशासन ने जो दावे किए थे, उनका असर कहीं नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि देश के टॉप 50 प्रदूषित शहरों में अपने फरीदाबाद का नाम भी शामिल हुआ है। प्रदूषित शहरों की लिस्ट में फरीदाबाद 25 वें स्थान पर है। यहां पीएम 2.5 का स्तर सामान्य से कई गुणा ज्यादा रहता है। इससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। यह दावा किया जा रहा है कि हरियाणा स्टेट पलूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ-साथ नगर निगम ने भी प्रदूषण कम करने की दिशा में खूब काम किया है। लेकिन आज शहर का हाल देखें तो जाम के कारण वाहनों से निकलने वाले धुएं, फैक्ट्री के धुएं, धूल आदि के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल की तुलना में प्रदूषण के मामले में फरीदाबाद की हालत और बिगड़ गयी है। प्रदूषण के मामले में हमेशा शुमार फरीदाबाद आपको बता दें कि फरीदाबाद का नाम हमेशा से ही प्रदूषण के मामले में टॉप-10 शहरों में शुमार रहता है। यहां पीएम 2.5 की मात्रा 300 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा रहती है, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। रिपोर्ट्स की मने तो शहर में प्रदूषण के तीन प्रमुख कारण हैं। यह कारण है पेट्रोल-डीजल के वाहनों की संख्या, फैक्ट्रियों का धुआं और सड़क किनारे पड़ी धूल। अक्टूबर से जनवरी तक प्रदूषण का ग्राफ इस कदर बढ़ जाता है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिवाली के आसपास पटाखों से निकलने वाले धुएं के कारण सारा प्रदूषण नीचे ही जम जाता है। इस कारण एक्यूआई में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इन उपायों से कम हो सकता है प्रदूषण प्रदूषण फैलाने में फ्यूल वाहनों की भूमिका 40 प्रतिशत है। इसलिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दे रही है। साथ ही प्रदूषण फैलने का बड़ा कारण ईंट-भट्ठे व क्रशर जोन भी है। क्रशर चलने के कारण टूटी सड़कें भी प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह है। हमारे यहां दो तरह की सड़कें बनाई जाती हैं एक तो तारकोल और दूसरी सीमेंटिड। इनमें से सीमेंटिड सड़क -प्रदूषण ज्यादा करती है। हाइवे सीमेंटिड बनी है तो टायर के घिसने से ज्यादा प्रदूषण होता है। हालांकि, हाइवे अब तारकोल से ज्यादा बनाए जाते हैं।

चीन को बड़ा झटका, 'अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग, चीन आंख उठाकर भी न देखे'; अमेरिका ने ड्रैगन को लगाई फटकार

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश सीमा मामले में भारत का समर्थन करते हुए चीन को कड़ी चेतावनी दी है. दरअसल, अमेरिका ने कहा कि हम अरुणाचल को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देते हैं और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार के हिस्से पर चीन के दावे को खारिज करते हैं। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग बिडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे चीन के किसी भी एकतरफा प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं। चीन ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अरुणाचल को अपना हिस्सा बताया था और राज्य पर दावा किया था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और हम सैन्य या नागरिक द्वारा किसी भी घुसपैठ या अतिक्रमण का

कड़ा विरोध करते हैं। अमेरिका ने चीन को लगाई फटकार इस सप्ताह की शुरुआत में चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग शियाओगांग ने कहा था कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है और बीजिंग कभी भी अरुणाचल प्रदेश को स्वीकार नहीं करता है। अब इस बयान पर अमेरिका ने चीन को फटकार लगाई है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है और इन दावों के तहत राज्य में भारतीय नेताओं के दौरे पर नियमित रूप से आपत्ति जताता है। बीजिंग ने इस इलाके का नाम भी जांगनान रखा है. पीएम ने किया सुरंग का उद्घाटन आपको बता दें कि 9 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल को राष्ट्र को समर्पित किया था. यह सुरंग रणनीतिक रूप से स्थित तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और सीमांत क्षेत्र में सैनिकों की बेहतर आवाजाही सुनिश्चित करेगी।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजों में दिल्ली सरकार द्वारा 4 सालों से फंड मुहैया न होने से दुखी कर्मचारियों ने आंदोलन का रास्ता पकडा

परिवहन विशेष। एस.डी.सेठी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित दिल्ली सरकार के पूर्ण रूप से वित पोषित 12 कॉलेज के सैंकडों कर्मचारी पिछले 4 सालों से समय पर पैसा ना मिलने से खासे परेशान हैं। अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा है। वह पिछले एक महीने से अपने हकों के लिए कॉलेजों के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। लाचार और बेहद परेशान सैंकडों कर्मचारियों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन (डूक्कू) के अध्यक्ष देवेन्द्र शर्मा, जनरल सेकेट्री रविंद्र पांडे, कॉलेज स्टाफ लैब एसोसिएशन के प्रेसीडेंट नंद किशोर, धर्मेंद्र ,शेखर चंद, राजेश एवं कुलदीप आदि के नेतृत्व में आज गुरूवार को आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में सुबह 10 बजे से धरना-प्रदर्शन किया। धरने में इकट्ठे सैकडों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए यूनियन अध्यक्ष देवेन्द्र शर्मा समेत तमाम पदाधिकारियों ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित 12 कॉलेजों जिनमें कालका जी स्थित एनडी कॉलेज, राजगुरू कॉलेज ऑफ अप्लाइड साईंस, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, केशव महाविद्यालय ,शहीद सुख देव कॉलेज आफ बिजनेस स्टडीज, अदिति महाविद्यालय, एमवी कॉलेज आफ एजूकेशन, भगिनी निवेदिता कॉलेज आफ एजूकेशन, अम्बेडकर कॉलेज, डीडीयू कॉलेज द्वारका, भास्कराचार्य कॉलेज द्वारका, और इंदिरा गांधी इंस्टीटयूट ऑफफिजिकल एजूकेशन, विकास पुरी शामिल है। यूनियन अध्यक्ष देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि ये तमाम 12 कॉलेज दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा वित पोषित हैं। पिछले 4 सालों से कभी भी समय पर दिल्ली सरकार द्वारा पैसा मुहैया नहीं किया गया है। समय पर सैलरी, समेत अन्य भत्ते तक के लिए स्टाफ मोहताज हो गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा इन 12 कॉलेजों के कर्मचारियों के साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। यूनियन प्रेसीडेंट देवेन्द्र शर्मा समेत तमाम कर्मचारी यूनियन नेताओ ने अपनी मुख्य मांगों को गिनाते हुए बताया कि कॉलेजों में सैलरी का नियमितीकरण तुरंत प्रभाव से किया जाए। समय पर तमाम अन्य भत्तों का भुगतान किया जाए। इसके अलावा इन कॉलेजों में सालों से बतौर कांट्रैक्ट कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नियमित किया जाए। अपनी सभी लंबित मांगों पर कारवाई के लिए सैंकडों कर्मचारियों ने दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिषी के आफिस तक रैली मार्च निकाला। मगर वहां के अधिकारियों ने मंत्री के तानाशाही आदेश की तामील पर गेट पर ताला ठोक दिया। और ज्ञापन तक लेने से मना कर दिया। इस बात से गुस्साए तमाम सैंकडों कर्मचारियों ने गेट के बाहर ही धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

गौतमबुद्ध नगर सीट से सपा का टिकट काटने का रहा है पुराना इतिहास, इससे पहले 2009 में भी किया था ऐसा

परिवहन विशेष न्यूज

समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर गौतमबुद्ध नगर सीट पर अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। पहले सपा ने डॉ. महेंद्र नागर को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था लेकिन बुधवार को सपा ने इस सीट पर महेंद्र नागर की जगह राहुल अवाना (Rahul Awana) को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब सपा ने ऐसा किया है। पहले भी पार्टी ऐसा कर चुकी है।

राजकुमार भाटी के इंकार के बाद सपा मुख्यालय में रविंद्र भाटी को फोन कर लखनऊ बुलाया गया, लेकिन पार्टी ने रविंद्र भाटी को टिकट देने के बचाए गठबंधन में शामिल कांग्रेस को सीट दे दी। कांग्रेस और सपा गठबंधन से समीर भाटी चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

नोएडा। सपा का लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी बदलने का पुराना इतिहास रहा है। सपा ने इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र भाटी को गौतमबुद्धनगर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था।

इसके बाद नामांकन से पहले उनका टिकट बदलकर गढ़ के पूर्व विधायक मदन चौहान को टिकट दे दिया था। इसका क्षेत्र में जबरदस्त विरोध हुआ, तो मदन चौहान ने स्वयं आगे आकर अपना टिकट वापस कर दिया। सपा को फिर से नरेंद्र भाटी को प्रत्याशी बनाना पड़ा।

2007 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने किया था ऐसा

वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने गौतमबुद्धनगर की दादरी सीट से पूर्व विधायक समीर भाटी को प्रत्याशी बनाया था। वह कई दिन तक चुनाव प्रचार कर इलाके में वोट मांगते रहे, लेकिन नामांकन से पहले उनका टिकट काटकर नोएडा के अशोक चौहान को दे दिया गया था।

इससे पार्टी में दो फाड़ हो गई। वहीं समीर भाटी रालोद से चुनाव लड़े। दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह 2012 के विधानसभा चुनाव में फकीर चंद्र नागर को दादरी विधानसभा से एक साल पहले यानी की 2011 में टिकट दिया गया था।

2017 के चुनाव में रविंद्र भाटी को दिया था टिकट

एक साल तक उन्होंने गांव गांव जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन नामांकन से पहले उनका भी टिकट काटकर राजकुमार भाटी को दे दिया गया। उस समय पार्टी दो फाड़ तो नहीं हुई लेकिन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में दादरी से सपा ने जलालपुर गांव के रहने वाले युवा और क्रांतिकारी नेता रविंद्र भाटी को टिकट दिया।

रविंद्र भाटी के साथ बड़ी संख्या में युवा वर्ग जुड़ा था। उनके पक्ष में माहौल बन ही रहा था कि नामांकन से पहले उनका भी टिकट काट दिया गया। राजकुमार भाटी को फिर से प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया।

जब रविंद्र भाटी को फोन कर लखनऊ बुलाया गया...

राजकुमार भाटी के इंकार के बाद सपा मुख्यालय में रविंद्र भाटी को फोन कर लखनऊ बुलाया गया, लेकिन पार्टी ने रविंद्र भाटी को टिकट देने के बचाए गठबंधन में शामिल कांग्रेस को सीट दे दी। कांग्रेस और सपा गठबंधन से समीर भाटी चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

चुनाव पर कितना पड़ेगा असर?

सपा ने अपने पुराने इतिहास को दोहराते हुए एक बार फिर लोकसभा सीट के लिए घोषित प्रत्याशी डा महेंद्र नागर का टिकट काटकर नोएडा के राहुल अवाना को दे दिया है। इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पार्टी में विरोध के स्वर फूटने लगे हैं।

कई बड़े नेताओं ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर कहा कि हर चुनाव में हाईकमान जिले में फजीहत कराता है। इसका विपरीत असर संगठन के कार्यकर्ताओं और कार्यों पर पड़ता है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि वह शीघ्र ही कोई बड़ा निर्णय लेंगे। सूत्रों का दावा है की कुछ लोग चुनाव से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं।

नोएडा के युवक से करीब 1 करोड़ की ठगी, निवेश कर कमाई का लालच देकर जालसाजों ने हड़पी रकम

परिवहन विशेष न्यूज

एक व्यक्ति ने उन्हें घर बैठे स्टाक मार्केट में निवेश कर कमाई का लालच देकर वाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा था। आरोपितों ने पीड़ित को कई कंपनियों में पैसा निवेश करने का लालच दिया। आरोपितों ने कमाई का लालच देकर कई बार में 97 लाख 40 हजार रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराए हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

नोएडा। सेक्टर-36 स्थित साइबर थाने को शिकायत में अनुपम अग्रवाल ने बताया कि वह सेक्टर-75 स्थित सोसायटी में रहते हैं। एक व्यक्ति ने उन्हें घर बैठे स्टाक मार्केट में निवेश कर कमाई का लालच देकर वाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा था।

आरोपितों ने पीड़ित को कई कंपनियों में पैसा निवेश करने का लालच दिया। राजीव मित्तल नाम के व्यक्ति ने खुद को दक्षिण पूर्व एशिया के फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स का प्रमुख बताकर निवेश के जरिये कमाई का लालच दिया। इसके बाद आरोपितों ने कमाई का लालच देकर कई बार में 97 लाख 40 हजार रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराए हैं।

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी अंजान व्यक्ति के कहने पर बहकावे में नहीं आए। बिना तहकीकात के कमाई के लालच में नहीं फंसे। अगर कोई कमाई के नाम पर निवेश के नाम पर कहता तो सतर्कता बरते।

30 वर्ष से गंगाजल की मांग कर रहे हैं लोग, खोड़ा में गंगाजल का बजट बनाकर शासन को भेजा गया था

इस गर्मी खोड़ा के 10 लाख लोगों को नहीं मिलेगा पानी, दूषित जल से ही बुझानी होगी प्यास

परिवहन विशेष न्यूज

खोड़ा की 10 लाख की आबादी 30 वर्ष से गंगाजल की मांग कर रही है। हालांकि डीपीआर बन गई है। लोगों को भूमिगत दूषित जल से ही प्यास बुझानी होगी। 26 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने खोड़ा को नगर पालिका परिषद को अमृत 2.0 योजना में शामिल कर दिया था।

गाजियाबाद। खोड़ा में गंगाजल की लाइन बिछाने के काम में देरी होने के कारण इस गर्मी भी लोगों को भूमिगत दूषित जल से ही प्यास बुझानी होगी। खोड़ा की 10 लाख की आबादी 30 वर्ष से गंगाजल की मांग कर रही है। हालांकि डीपीआर बन गई है। कागजी प्रक्रिया को जमीन पर उतारने की कोशिश चल रही है।

गंगाजल के लिए बनाया गया था 253.14 करोड़ बजट

साल 2018 में जल निगम ने खोड़ा में गंगाजल का बजट बनाकर शासन को भेजा गया था। यह बजट तब पास नहीं हुआ था। 26 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने खोड़ा को नगर पालिका परिषद को अमृत 2.0 योजना में शामिल कर दिया था।

इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लखनऊ में बैठक बजट पर चर्चा हुई थी। इस योजना के तहत गंगाजल के लिए 253.14 करोड़ रुपये बजट बनाया गया था।

योजना के तहत नोएडा विकास प्राधिकरण से 50 एमएलडी पानी खोड़ के लिए लिया जाएगा। पेयजल लाइन से घर-घर तक पहुंचेगी। जल निगम द्वारा इसकी दोबारा से डीपीआर बनाकर शासन भेजी गई थी। गंगाजल की डीपीआर 253.14 करोड़ की बजाय 208 करोड़ रुपये की बनी थी।

डीपीआर और बजट की मिल चुकी है स्वीकृति

शासन में प्रशासनिक स्तर से डीपीआर और बजट की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके बाद भी फाइल अटकी हुई है। डीपीआर बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि इस बार गंगाजल की मांग उनकी पूरी हो जाएगी लेकिन उनकी उम्मीदों पर फिरता नजर आ रहा है।

अचार संहिता लागू होने से पेयजल लाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि इस गंगाजल लाइन बिछाने में हो रही देरी के कारण भूमिगत जल स्तर गिर रहा है। इस काम को जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि अब चुनाव के बाद ही काम शुरू होगा।

स्नेक वेनम मामले में PFA अधिकारी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी, पंजाब एंड हरियाणा HC में दायर की याचिका

परिवहन विशेष न्यूज

एल्विश सांप प्रकरण में जिला अदालत में याचिका दायर कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में याचिकाकर्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता कहना है कि उन्हें इंटरनेट मीडिया पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है।

गुरुग्राम। एल्विश सांप प्रकरण में जिला अदालत में याचिका दायर कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में याचिकाकर्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता कहना है कि उन्हें इंटरनेट मीडिया पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही केस वापस ना लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले में अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी।

सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा दबाव

पीपल फार एनिमल के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता के अधिवक्ता अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि इस मामले में डीजीपी हरियाणा, गृह मंत्रालय, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम और थाना प्रभारी बादशाहपुर को पार्टी बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को लगातार सोशल मीडिया पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई जसजीत सिंह बेदी की बेंच में चल रही है।

याचिकाकर्ता सौरव गुप्ता ने बताया कि उन्हें इंटरनेट मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने एक गाने में दूसरे देश के सांप के इस्तेमाल करने पर एल्विश यादव पर कार्रवाई करने के लिए गुरुग्राम अदालत में याचिका दायर की थी।

पांच मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत में पत्र दाखिल कर जान का खतरा बताया था। इस पर अदालत ने पुलिस को जांच करने के निर्देश दिए थे। गुरुग्राम अदालत में इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा की अदालत में चल रही है। इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई है।

ताली-थाली और लॉकडाउन से सब कुछ ठहर जाने के 68 दिन

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

22 मार्च को 14 घंटे का जनता कर्फ्यू और 22 मार्च को ही सायंकाल ताली, थाली, घंटी बजाने के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान को भरपूर समर्थन मिला पर लोग उस समय तक कोरोना की भयावहता को लेकर इतने गंभीर नहीं दिखे।

कोरोना के कारण देश दुनिया में सब कुछ थम जाने का दौर आज तो ना भूतो ना भविष्यती जैसा लग रहा है पर जिन्होंने कोरोना की भयावहता से गुजरने वालों के लिए आज भी यह किसी इतिहास की अब तक की किसी त्रासद घटना से कम नहीं है। जब रक्त बीज की बात की जाती है तो कपोल कल्पना से कम नहीं लगती पर जिन्होंने कोरोना का नजदीक से देखा और भुगता है वह जानते हैं कि राक्षस रक्त बीज से कम नहीं था कोरोना वायरस। रक्त बीज में भी तो यही है कि उसके रक्त की बूंद जहां भी गिरेगी वहीं नया राक्षस पैदा हो जाएगा। लगभग यही कुछ देखा है देश दुनिया के लोगों ने कोरोना काल में। गरीब हो या अमीर, साधन संपन्न हो या साधन विहीन, झोपड़ी वासी हो या महल में निवास करने वाला, लगभग सभी कोरोना के उस दौर में घर की चार दीवारी में बंद हो कर रह गए। कोविड 19 से दुनिया में सब कुछ थमा कर रख दिया। हालात ही ऐसे थे। संपर्क ही जान लेवा बन रहा था। सेनेटाइजर, मास्क, डिस्टेंस, चार दीवारी, क्वरंटाइन और बस यही कुछ देखने सुनने को मिलता था तो अस्पतालों में कोरोना के कारण होने वाली क्या अपने क्या पराये की मौत। हालात लगभग सारी दुनिया में ऐसे ही रहे। 2019 में चीन से सारी दुनिया को अपने आगोश में लेने वाले कोरोना का हमारे देश में चीन के बुहान से केरल के रास्ते 30 जनवरी, 20 को प्रवेश हुआ और 24 मार्च 2020 जिस दिन से लॉकडाउन की शुरुआत हुई उस दिन तक कोरोना पोजेटिव के 519 मामलें सामने आ चुके थे और 19 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके थे।

कोरोना के जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन को चार साल पूरे होने जा रहे हैं पर 24 मार्च को लॉकडाउन का दिन याद करके आज भी सिहरन उठ जाती है। 22 मार्च को 14 घंटे का जनता कर्फ्यू और 22 मार्च को ही सायंकाल ताली, थाली, घंटी बजाने के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान को भरपूर समर्थन मिला पर लोग उस समय तक कोरोना की भयावहता को लेकर इतने गंभीर नहीं दिखे। लोगों ने ताली थाली के आह्वान का मखौल भी उड़ाया और हालात की भयावहता को समझ नहीं पाये। इसे पोंगा पंथी और ना जाने क्या क्या कहा जाने लगा। इसके बाद ज्योंही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से मुखातिब होते हुए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की तो एक बार तो सब सकते में ही आ गये ।पर जिस तरह से लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामलें दिन दूने रात चौगुने होने लगे और कोरोना पीड़ति अपनों से ही दूर होते गए तब इसकी भयावहता को समझा जाने लगा। सरकार ने बार बार सेनेटाइजर के उपयोग, मास्क के लगातार उपयोग और दूरी का संदेश दिया उसका असर आज समझ में आने लगा है। सरकार एसओपी जारी कर हालात को काबू में करने में जुट गई। चिकित्सकों, चिकित्साकर्मियों, पेरा मेडिकल स्टॉफ ने जान की वाजी लगा कर सेवा में जुट गए। हालात यहां तक देखे गए कि सेवा में लगे लोग में मौत का ग्रास बनने लगे। दूसरी लहर आते आते तो हालात यहां तक बदतर हो गए कि अस्पतालों में जीवन रक्षक वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की उपलब्धता की दिक्कत आ गई। यह सब तो एक और वहीं दूर दराज में रहने वाले लोग जो भी साधन मिला यहां तक कि पैदल ही परिवार के साथ काम धंधा छोड़कर अपने गांव की और रुख करने लगे और हजारों किलोमीटर पैदल ही निकल पड़े। सरकार के सामने इन लोगों के लिए यात्रा के दौरान खाने पीने ठहरने और नियत स्थान तक पहुंचाने की समस्या हो गई वह अलग। इसी तरह से विदेशों में अध्ययन कर रहे या रह रहे लोगों को सुरक्षित लाना भी सरकार के सामने किसी चुनौती से कम नहीं था। अखबारों में आक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर के अभाव में अस्पताल परिसर या सड़क पर ही दम तोड़ते लोगों, अंतिम क्रिया तक में शामिल नहीं होने तक का दुख जैसे कई अनुभव इस दौरान देखने को मिले। बीस-पचास आदमियों में शादी की कल्पना को भी इसी दौरान साकार होते देखा गया। शुरुआती दौर में तो कोरोना वैक्सिन की बात करना ही दूर की बात थी तो बाद में वैक्सिन के पहले दौर के दौरान जिस तरह से वैक्सिन को भी राजनीति की भेंट चढ़ाने के प्रयास हमने देखे हैं। खैर यह दूसरी बात है कि देशवासियों को निःशुल्क कोरोना वैक्सिनेशन की दो डोज और दुनिया के देशों को वैक्सिन उपलब्ध कराने की हमारी पहल को सारी दुनिया ने सराहा।

खैर यह तो तस्वीर का एक पहलू रहा। दरअसल मुद्दे की बात यह है कि आज भले ही हम लॉकडाउन की चार साल की बात कर रहे हैं पर 68 दिन का यह लॉकडाउन ही कोरोना में सही मायने में जीवनदायी सिद्ध हो सका। 25 मार्च से 14 अप्रैल, फिर 15 अप्रैल से 3 मई, उसके बाद 4 मई से 17 मई और फिर 18 मई, 20 से 31 मई, 20 तक के 68 दिन घर की चार दीवारी में बंद रहकर गुजारने का अलग ही अनुभव रहा है। वर्क फ्रॉम होम से लेकर ऑनलाइन स्टडी तक का यह दौर रहा और आज भी भले ही कम हो गया हो पर ऑनलाइन स्टडी व वर्क फ्रॉम होम कमोबेस चल रहा है। हांलाकि कोरोना काल को भी लोगों ने भुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, वेंटिलेटर बेड और आक्सीजन सिलेण्डर, कंसरट्रेटर, ऑक्सीजन बेड और दवाओं की कालाबाजारी भी खूब देखने को मिली। खैर मानवता के दुश्मन तो हर युग में रहते आये हैं। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन का दौर हमने ही देखा हो अपितु दुनिया के अधिकांश देशों में लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के माध्यम से ही कोरोना के फैलाव को रोकने के प्रयास सफल हो सके। भूलना नहीं चाहिए कि इंग्लेण्ड के तत्कालीन प्रधानमंत्री को कोरोना प्रोटोकाल की पालना में कोताही के कारण ही भले ही उन्होंने लाख सफाई दी, अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। कोरोना प्रभावित की सूचना पर जिस तरह से उस घर से प्रभावित को अस्पताल ले जाते थे व घर के बाहर नोटिस चस्पा करने और अलग थलग होने के हालात कितने त्रासद होते थे यह कल्पना का विषय ही है। मामूली बुखार व संभावना पर ही घर में ही अलग थलग क्वारंटाइन होने को भुगतने वाले ही जानते हैं। दिन रात मौत का भय उस व्यक्ति या परिवार से पूछा जाए जो इन हालातों से गुजरे हैं।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि कोरोना के कारण 30 जनवरी, 2020 से 5 मार्च, 24 तक भारत में ही 3 करोड़ 37 लाख 66 हजार 707 मामलें सामने आ चुके हैं और 4 लाख 48 हजार 339 अपनों को खो चुके हैं। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसके अलावा सरकार के जनता कर्फ्यू व उसके बाद 68 दिन के लॉक डाउन नहीं होता तो कोरोना से प्रभावित होने वाले और इसके कारण होने वाली मौतों की संख्या अकल्पनीय होती। सरकार की सख्ती, लोगों की अवेयरनेस के बावजूद भी जो कोरोना काल के हालात देखें उसको याद करके ही सिहरन होने लगती है। ऐसे में यह कहने में दो राय नहीं होनी चाहिए कि कोरोना रुपी रक्त बीज का असर कम करने में अन्य के साथ ही लॉकडाउन की प्रमुख भूमिका रही है। आने वाली पीढ़ियों को भले ही यह अतिशयोक्तिपूर्ण लगे पर जिन्होंने देखा, भोगा और अपनों को खोया है वे कोरोना को भूल ही नहीं सकते। ताली-थाली की भले ही मजाक में लिया जाए पर यह और लॉकडाउन ने जिंदगियां बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

Citroen eC3: सिट्रॉएन की इलेक्ट्रिक हैचबैक Crash Test में हुई फेल, Global NCAP से मिली जीरो रेटिंग

परिवहन विशेष न्यूज

फ्रांस की वाहन निर्माता Citroen की ओर से भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक हैचबैक कार के तौर पर eC3 को ऑफर किया जाता है। लेकिन यह गाड़ी सुरक्षा के मामले में काफी पीछे रह जाती है। Global NCAP की ओर से किए गए क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी को जीरो रेटिंग मिली है। रिपोर्ट में और क्या जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। Citroen की ओर से देश में eC3 को इलेक्ट्रिक हैचबैक के तौर पर ऑफर किया जाता है। लेकिन सेफ्टी के लिए किए गए Crash Test में Global NCAP ने इस कार को जीरो रेटिंग दी है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि कंपनी की ओर से इस कार में किस तरह के सेफ्टी फीचर्स को दिया जाता है।

Crash Test में फेल हुई Citroen eC3

ग्लोबल एनसीएपी की ओर से हाल में किए गए क्रैश टेस्ट में फ्रेंच कार निर्माता की इलेक्ट्रिक कार eC3 बुरी तरह से फेल हो गई है। संस्थान की ओर से इस कार को सेफ्टी के लिए जीरो स्टार मिले हैं। ग्लोबल एनसीएपी की आधिकारिक वेबसाइट पर इस कार से जुड़ी जानकारी दी गई है। जिसके मुताबिक एडल्ट की सुरक्षा में इसे जीरो और बच्चों की सुरक्षा के लिए इस कार को टेस्ट के बाद एक स्टार मिला है। खास बात यह थी कि जिस गाड़ी का टेस्ट किया गया है वह भारत में बनी हुई कार है।

टेस्ट में मिला कैसा स्कोर

ग्लोबल एनसीएपी की ओर से किए गए क्रैश टेस्ट में सिट्रॉएन की इस कार को अडल्ट की सुरक्षा में 34 में से सिर्फ 20.86 पाइंट मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के सिर और गर्दन पर सुरक्षा बेहतर थी। लेकिन छाती पर सुरक्षा काफी कम थी। वहीं साइड इम्पैक्ट टेस्ट में सिर पर मार्जनल और छाती पर थोड़ी बेहतर सुरक्षा मिली। टेस्ट के मुताबिक बॉडीशेल इंटीग्रिटी स्टेबल थी और दरवाजों पर साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन में भी कार बेहतर रही। एडल्ट टेस्ट के साथ ही बच्चों की सुरक्षा में भी कार को 49 में से 10.55 अंक मिले।

कैसे थे सेफ्टी फीचर

ग्लोबल एनसीएपी की ओर से जिस कार को टेस्ट किया गया। उसमें स्टैंडर्ड तौर पर दो एयरबैग दिए गए थे। इसके अलावा टेस्ट की गई कार में ईएससी भी नहीं था।

M&M और अडानी टोटल एनर्जीस ने मिलाया हाथ, ईवी चार्जिंग इंफ्रा मजबूत करने की तैयारी

Mahindra & Mahindra ने गुरुवार को कहा कि उसने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल करने के लिए Adani Total Gas की एक यूनिट के साथ समझौता किया है। मुंबई स्थित वाहन निर्माता ने कहा कि MOU देश भर में एक विस्तृत ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए रोडमैप तय करता है। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Mahindra & Mahindra ने गुरुवार को कहा कि उसने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल करने के लिए Adani Total Gas की एक यूनिट के साथ समझौता किया है। इसको लेकर अदानी टोटल एनर्जी ई-मोबिलिटी लिमिटेड (ATEL) ने इस संबंध में एक MOU साइन किया है। आइए, पूरी खबर के बारे जान लेते हैं।

EV Charging Infra का होगा विस्तार

मुंबई स्थित वाहन निर्माता ने कहा कि MOU देश भर में एक विस्तृत ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए रोडमैप तय करता है। इसके अलावा, साझेदारी में ग्राहकों को डिस्कवर, अवेसबिलिटी, नेविगेशन और लेनदेन को कवर करने वाले चार्जिंग नेटवर्क तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए ई-मोबिलिटी समाधान भी शामिल होंगे। इसमें कहा गया है कि इस सहयोग से, इलेक्ट्रिक वाहन XUV400 ग्राहकों के पास अब 1,100 से अधिक चार्जर तक पहुंच होगी।

M&M के अध्यक्ष - ऑटोमोटिव डिवीजन विजय नाकरा ने कहा कि यह गठबंधन ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में एक आधारशिला है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे ग्राहकों को यूनिक ईवी एक्सपीरिएंस के लिए चार्जिंग नेटवर्क और डिजिटल इंटीग्रेशन तक निर्बाध पहुंच का आनंद मिले।

Electric Vehicles पर जोर

उन्होंने कहा कि पार्टनर नेटवर्क के साथ कस्टमर एक्सपीरिएंस को बढ़ाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, कंपनी ईवी इंफ्रा को व्यापक बनाने के लिए सक्रिय रूप से कई साझेदारों को शामिल कर रही है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया जा सके।

बीएमडब्ल्यू ने लॉन्च की नई इलेक्ट्रिक iX xDrive50, जानें कितनी है कीमत और कैसे हैं फीचर्स

जर्मनी की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी BMW ने भारतीय बाजार में नई इलेक्ट्रिक गाड़ी iX xDrive50 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की ओर से इस नई इलेक्ट्रिक गाड़ी में किस तरह के फीचर्स को जा रहा है। BMW की नई गाड़ी में कितनी रेंज ऑफर की जा रही है। इसे किस कीमत पर खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में वाहन निर्माताओं की ओर से लगातार नए इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च किया जा रहा है। इसी क्रम में BMW की ओर से नई इलेक्ट्रिक एसयूवी iX xDrive50 को लॉन्च कर दिया गया है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि कंपनी की ओर से इस गाड़ी को किस कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं, इसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं।

BMW ने लॉन्च की iX xDrive50

बीएमडब्ल्यू की ओर से iX xDrive50 इलेक्ट्रिक गाड़ी को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी में कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ही सेफ्टी फीचर्स को भी दिया गया है।

क्या हैं खूबियां

BMW की ओर से लॉन्च की गई iX xDrive50 के इंटीरियर को इस तरह से बनाया गया है, जिससे यात्री को ज्यादा से ज्यादा आराम मिल सके। कंपनी ने लाउंज की तरह मिलने वाले आराम को ध्यान में रखते हुए इसका इंटीरियर डिजाइन किया है। इसके साथ ही इसमें पैनारोमा ग्लास रूफ, एक्टिव सीट वेंटिलेशन, एंबिएंट लाइट, मल्टी वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मसाज वाली सीटें, लेदर अपहोल्स्ट्री, 22 इंच के नए और हल्के अलॉय व्हील्स, फ्रेमलेस विंडो, एयर सस्पेंशन, एलईडी हेडलाइट, की-लैस एक्सेस, फोर जोन ऑटो एसी, 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, 14.9 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले, थ्री डी मैप के साथ नेविगेशन और हरमन कार्डन के 18 स्पीकर के साथ ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कितनी है सुरक्षित

कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में रिवर्सिंग असिस्टेंट, पार्किंग असिस्टेंस प्लस, 360 डिग्री कैमरा, एबीएस, ब्रेक असिस्ट, डायनैमिक ब्रेकिंग लाइट, डीएससी, टीपीएमएस, ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट, लेन चेंज वॉर्निंग, लेन चेंज असिस्ट, एक्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ स्टॉप और गो फंक्शन, पैदल यात्रियों की सुरक्षा जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

कितनी है रेंज

BMW की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में कंपनी की ओर से 111.5 kWh की क्षमता की बैटरी पैक को दिया गया है। जिससे 635 किलोमीटर की WLTP रेंज मिलती है। एसयूवी को 195 kW डीसी चार्जर से सिर्फ 35 मिनट में 10 से 80 फीसदी चार्ज किया जा सकता है। जिसके बाद इसे 145 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसमें लगी मोटर से 523 हॉर्स पावर और 765 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिससे 4.6 सेकेंड में जीरो से 100 किलोमीटर की स्पीड हासिल की जा सकती है।

कितनी है कीमत

बीएमडब्ल्यू की इस नई इलेक्ट्रिक गाड़ी को कंपनी ने 1.39 करोड़ रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है।

Volkswagen ID.4 इस साल के अंत तक हो सकती है लॉन्च, ब्रांड ने पेश की अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार

परिवहन विशेष न्यूज

Volkswagen ID.4 पूरी तरह से निर्मित यूनिट(CBU) के रूप में भारत आएगी इसलिए इसकी कीमत अधिक होने की उम्मीद है। ये इलेक्ट्रिक कार अधिकतम 299 बीएचपी की पावर और 499 एनएम का पीक टॉर्क वाले पावरट्रेन के साथ आ सकती है। ID.4 EV केवल 6 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Volkswagen India ने जयपुर में आयोजित अपनी Annual Brand Conference में ID.4 Electric Car को पेश किया है। ब्रांड ने पुष्टि की है कि वे 2024 के अंत तक भारतीय बाजार में इसे लॉन्च कर देंगे। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

किसे देगी टक्कर ?

Volkswagen ID.4 पूरी तरह से निर्मित यूनिट(CBU) के रूप में भारत आएगी, इसलिए इसकी कीमत अधिक होने की उम्मीद है। इंडियन मार्केट में ये Kia EV6 और Hyundai Ioniq 5 को टक्कर देगी। पिछले साल अप्रैल में ब्रांड ने पहली बार भारत में ID.4 को अनवील किया था।

पावरट्रेन और परफॉरमेंस

ये इलेक्ट्रिक कार अधिकतम 299 बीएचपी की पावर और 499 एनएम का पीक टॉर्क वाले पावरट्रेन के साथ आ सकती है। ID.4 EV केवल 6 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 180 किमी प्रति घंटे तक सीमित है।

बैटरी और रेंज

उम्मीद है कि Volkswagen ID.4 को 82 kWh बैटरी पैक के साथ ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जाएगा। सिंगल चार्ज पर ये ईवी 500KM तक की रेंज देने में सक्षम होगी।

Taigun को मिला GT Plus Sport और Taigun GT Line वेरिएंट

ब्रांड ने आज टाइगुन को दो नए वेरिएंट - जीटी लाइन और जीटी स्पोर्ट के साथ अपडेट किया है। दोनों में कॉस्मेटिक अपडेट दिया गया है, जो एसयूवी को अधिक स्पोर्टी और आकर्षक बनाते हैं।

VW Taigun को पहली बार सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और ये वर्तमान में दो ट्रिम लेवल के साथ आती है। इसमें डायनेमिक लाइन और परफॉर्मेंस लाइन शामिल है। परफॉर्मेंस लाइन में जीटी वेरिएंट शामिल है, जबकि डायनामिक लाइन में कम्फर्टलाइन, हाईलाइन और टॉपलाइन शामिल हैं।

मर्सिडीज बेंज GLC को मिला प्लग इन वैरिएंट, जानिए पहले से कितनी बदली और इंडिया में कब होगी लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

कुल 3 ट्रिम्स- स्टैंडर्ड एक्सक्लूसिव और पिनेकल में उपलब्ध है। जीएलसी का ये Plug-in Hybrid वेरिएंट डिजाइन के मामले में लगभग समान ही दिखता है। जर्मन लग्जरी कार निर्माता ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यह भारत में कब आ सकती है। हालांकि GLC भारत में ब्रांड के सबसे अधिक बिकने वाले मॉडलों में से एक है।

नई दिल्ली। Mercedes-Benz ने GLC SUV का Plug-in Hybrid वेरिएंट लॉन्च किया है। Mercedes-Benz GLC350e 4Matic प्लग-इन हाइब्रिड नाम से एक नया वेरिएंट GLC पोर्टफोलियो में शामिल हो गया है। इसे साल के अंत तक ग्लोबली सेल करना शुरू कर दिया जाएगा।

वेरिएंट और कलर ऑप्शन

Mercedes-Benz GLC350e कुल 3 ट्रिम्स- स्टैंडर्ड, एक्सक्लूसिव और पिनेकल में उपलब्ध है। जीएलसी का ये Plug-in Hybrid वेरिएंट डिजाइन के मामले में लगभग समान ही दिखता है। ये 11 अलग-अलग एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जबकि एसयूवी को 8 यूनिक व्हील डिजाइन भी मिलते हैं।

इंटीरियर और फीचर्स

केबिन के अंदर इस लग्जरी एसयूवी में हीटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 11.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर लिफ्टगेट, ब्लाइंड-स्पॉट असिस्ट और एडेप्टिव हाई जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं।

इसके अलावा एक्सक्लूसिव ट्रिम बर्मेस्टर 3डी सराउंड साउंड ऑडियो सिस्टम, एंबिएंट लाइटिंग और इल्युमिनेटड डोर सिल्स के साथ आता है। पिनेकल ट्रिम में हेड-अप डिस्प्ले, नॉइज और हीट-इंसुलेटिंग ग्लास, अपग्रेडेड डिजिटल लाइट हेडलैंप के अलावा बाकी सारे फीचर्स मिलते हैं। GLC का नया वेरिएंट 13 अपहोल्स्ट्री विकल्पों के साथ उपलब्ध है।

इंजन और परफॉरमेंस

GLC350e 4मैटिक प्लग-इन हाइब्रिड को पावर देने वाला 2.0-लीटर चार-सिलेंडर इंजन है, जो 132 bhp जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर और 24.8 kWh बैटरी पैक के साथ जुड़ा है। हाइब्रिड पावरट्रेन 308 bhp की अधिकतम पावर और 550 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है। कार निर्माता का दावा है कि 442 एनएम पर कुल टॉर्क आउटपुट का 80 प्रतिशत तुरंत इलेक्ट्रिक मोटर से उपलब्ध होता है। दावा है कि यह एसयूवी 6.6 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है।

जर्मन लग्जरी कार निर्माता ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यह भारत में कब आ सकती है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि GLC भारत में ब्रांड के सबसे अधिक बिकने वाले मॉडलों में से एक है, हाइब्रिड वेरिएंट के भी यहां लॉन्च होने की उम्मीद है।

सेहत को समझिए साहब

डॉ. आशीष वशिष्ठ

होटल या रेस्टोरेंट में जो खाना आपको सर्व होता है, उसमें साफ-सफाई का तो ध्यान रखा जाता है, लेकिन वह स्वास्थ्यकर है या नहीं, इससे होटल वालों को कोई मतलब नहीं है। सलाद को भूनकर, पकाकर या फ्राई करके सर्व करने का रिवाज पिछले कुछ सालों में ही शुरू हुआ है, यह बिल्कुल भी स्वास्थ्यकर नहीं है।

हम मानें या न मानें, हमें मालूम हो या न हो, पर हम किसी न किसी चिंता से, परेशानी से, दुख से, पछतावे से, नफरत से, गिले वाले विचार से घिरे ही रहते हैं। ये विचार ही हमारी मानसिक व्याधियों का कारण बनते हैं जो बाद में शारीरिक बीमारी के रूप में बदल जाते हैं और जीवन दूभर बना देते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग इनकी रोकथाम का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक अनुभवी स्पिरिचुअल हीलर जीवन में इतनी उमंग भर सकता है और हमें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना सकता है कि शेष जीवन में हमें इसकी जरूरत बार-बार नहीं पड़ती और जीवन खुशहाल बना रहता है। जरूरत है तो बस इतनी कि हम अपने इस प्राचीन ज्ञान को समझें और जीवन में उतारें'

हम सब जानते हैं कि हम प्रचार के युग में जी रहे हैं, मार्केटिंग के युग में जी रहे हैं।

दरअसल, हम झूठे प्रचार के युग में जी रहे हैं। हम शोरगुल भरे मनोरंजन के युग में जी रहे हैं और एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सुविधा को खुशी मान लिया गया है। इससे हमारा जीवन दूषित हो गया है और हमारा स्वास्थ्य इस हद तक खतरे में है कि पैदा होने वाले हर नए बच्चे में से 90 प्रतिशत बच्चे पैदाइशी बीमार होते हैं। यह इतना खतरनाक सच है कि हमें इसकी गंभीरता को समझना ही होगा वरना आज हम युवाओं के देश के रूप में जाने जाते हैं, तो आने वाले दस वर्षों के बाद हम बीमार युवाओं के देश के रूप में पहचाने जाएंगे। आज भी, जी हां, आज भी 90 प्रतिशत वयस्क, प्रौढ़ और बुजुर्ग किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं और या तो लगातार दवाई ले रहे हैं या उन्हें पता ही नहीं है कि उनके शरीर में कोई रोग चुपचाप बढ़ता जा रहा है। पैकेज्ड फूड में सुविधा तो है ही, इसके एक खास हिस्से को 'हैल्दी फूड', यानी सेहतमंद भोजन के रूप में पेश किया जा रहा है और शहरी आबादी का बड़ा हिस्सा इसकी लपेट में है। यह भोजन, भोजन नहीं है, जहर है, इसे स्वास्थ्यकर कहना तो अपराध ही है। आधुनिक जीवन का शैदाई उच्च वर्ग और शहरी युवा, आउटिंग के नाम पर, या स्वाद और बदलाव के नाम पर अक्सर होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। होटल व्यवसाय में कमरों के किराए से उतनी आमदनी नहीं होती जितनी कि होटल में ठहरने वालों को भोजन खिलाकर होती है।

होटल या रेस्टोरेंट में जो खाना आपको सर्व होता है, उसमें साफ-सफाई का तो ध्यान रखा जाता है, लेकिन वह स्वास्थ्यकर है या नहीं, इससे होटल वालों को कोई मतलब नहीं है। सलाद को भूनकर, पकाकर या फ्राई करके सर्व करने का रिवाज पिछले कुछ सालों में ही शुरू हुआ है, यह बिल्कुल भी स्वास्थ्यकर नहीं है। इसी तरह 'हनी चिली कौलिफ्लावर' या 'हनी पटैटो' जैसे स्नैक जिनमें शहद है और उन्हें किसी भी रूप में पकाया गया है, वो स्वादिष्ट तो हैं, पर स्वास्थ्यकर नहीं हैं। भोजन में एक साथ रोटी और चावल दोनों खाना स्वास्थ्यकर नहीं है। खुद ही सोचिए कि कौनसा होटल-रेस्टोरेंट वाला आपको ये बताएगा? बुरी बात यह है कि खुद शैफ भी इस सच से वाकिफ नहीं हैं।

इससे भी ज्यादा दुख की बात और क्या होगी कि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के अध्यापक तक यह समझने की कोशिश नहीं करते कि भोजन में किस-किस खाद्य पदार्थ को एक साथ खाना हानिकारक हो सकता है। अज्ञान की पराकाष्ठा इस हद तक है कि हम खाना खाते नहीं हैं, निगलते हैं। नियम यह है कि हर कौर को इतना चबाया जाए कि वह पानी सरीखा हो जाए। अक्सर हम इस भुलावे में रहते हैं कि हमने चबा लिया, लेकिन कभी आप बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग दस सैकेंड तक चबाने के बाद हम चपाती का कौर निगल लेते हैं, जबकि एक कौर को पूरा चबाने के लिए 35 से 45 सैकेंड का समय आवश्यक होता है। चावल को तो हम अक्सर 5-6 सैकेंड में ही निगल लेते हैं। भोजन पूरा न चबाया जाए तो वह पचता नहीं है और उसका बहुत सा हिस्सा हमारे शरीर में ही रह जाता है जो सड़ता रहता है और कई बीमारियों का कारण बनता है।

अक्सर हमें मालूम ही नहीं होता कि अपनी लापरवाही के कारण हम अपने शरीर को कूड़ाघर बना रहे हैं। ऐसे माता-पिता के बच्चे जन्म से ही किसी न किसी बीमारी के बीज लेकर पैदा होते हैं। सेहत को लेकर हम एक और भुलावे में हैं कि अगर हम स्वास्थ्यकर भोजन खाएं और नियमित व्यायाम करें, तो हमारी सेहत ठीक रहेगी। अच्छी सेहत के लिए स्वास्थ्यकर भोजन और नियमित व्यायाम तो आवश्यक है ही, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। अच्छी नींद, अच्छे रिश्ते और अच्छी सोच भी सेहत को प्रभावित करते हैं। नींद पूरी न हो पाए तो धीरे-धीरे हम ऊर्जा खोते चले जाते हैं। हमारे आपसी रिश्तों में कड़वाहट हो या जीवन में अच्छे दोस्त न हों, तो हम खुश नहीं रह सकते। रिश्तों की कमजोरी हमारी खिसियाहट का कारण बनती है जो अंततः सेहत के लिए नुकसानदायक है। सबसे बढक़र हमारी सोच हमें प्रभावित करती है। हमारा हर विचार एक नई किस्म की वाइब्रेशन पैदा करता है, जो हमारे दिल और दिमाग को प्रभावित करता है। हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारे दिलो-दिमाग में भरी हुई शिकायतें, नफरत, गुस्सा, गिला, पछतावा जैसी भावनाएं हमारे अवचेतन मन में गहरे पैठ गई हैं तो वो किसी न किसी शारीरिक रोग के रूप में उभर कर आएंगी। चिकित्सा विज्ञान की शोध यह कहती है कि हमारी अधिकांश शारीरिक बीमारियों का कारण हमारी मानसिक व्याधियां हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण हम इन भावनाओं के नुकसान को नहीं समझते और लापरवाही का जीवन जीते हैं जो आखिरकार किसी गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है। थोड़ा सा भी बुखार हो तो हम दवाई खा लेते हैं। साधारण बुखार कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि शरीर में गंदगी जमा है, सड़ रही है, उसे बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन हम दवाई लेकर संदेश को दबा देते हैं, बुखार दब जाता है, लेकिन गंदगी अंदर ही रहने के कारण बीमारी चुपचाप बढ़ती रहती है। शूगर, बीपी जैसी बीमारियों में हम अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के बजाय रोज एक गोली खाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर दवाई का कोई न कोई साइड इफैक्ट होता है और यह दवाई ही एक नई बीमारी का कारण बन रही है, जो अगले 10-15 साल के बाद और भी खतरनाक रूप में उभरेगी।

अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि जैसे हम शारीरिक बीमारियों के लिए ब्लड टैस्ट और चेकअप करवाते हैं, वैसे ही मानसिक व्याधियों से बचने के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग से दिल और दिमाग की सफाई भी करवाते रहें। स्पिरिचुअल हीलिंग हमें अच्छी नींद लेने, खुश रहने और रिश्ते मजबूत बनाने में सहायक होती है। अगर हम स्वास्थ्यकर भोजन लें, नियमित रूप से हल्का-फुल्का व्यायाम करते रहें और स्पिरिचुअल हीलिंग से दिल और दिमाग की सफाई भी करवा लें। स्पिरिचुअल हीलिंग से हम खुशियों और खुशहाली से भरपूर एक आनंददायक जीवन जी सकते हैं। हम मानें या न मानें, हमें मालूम हो या न हो, पर हम किसी न किसी चिंता से, परेशानी से, दुख से, पछतावे से, नफरत से, गिले वाले विचार से घिरे ही रहते हैं। ये विचार ही हमारी मानसिक व्याधियों का कारण बनते हैं जो बाद में शारीरिक बीमारी के रूप में बदल जाते हैं और जीवन दूभर बना देते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग इनकी रोकथाम का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक अनुभवी स्पिरिचुअल हीलर जीवन में इतनी उमंग भर सकता है और हमें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना सकता है कि शेष जीवन में हमें इसकी जरूरत बार-बार नहीं पड़ती और जीवन खुशहाल बना रहता है। जरूरत है तो बस इतनी कि हम अपने इस प्राचीन ज्ञान को समझें और जीवन में उतारें।

संपादक की कलम से

सरकारी बसें कितनी आगे

सही समय पर प्रशासनिक दखल के परिणाम किस तरह बेहतर हो सकते हैं, इसका एक उदाहरण एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने पेश किया है। वह डीटीसी के साथ एक अनुबंध करके न केवल दिल्ली जा रही सरकारी बसों के लिए उनके राजघाट परिसर में पार्क करने की व्यवस्था कर रहे हैं, बल्कि वहां ड्राइवर-कंडक्टरों के लिए विश्राम की उचित व्यवस्था भी कर रहे हैं। इस तरह एचआरटीसी सालाना अपने व्यय में करीब दो करोड़ की बचत करते हुए भविष्य के रास्ते खोज रही है। यह दीगर है कि सरकारी बसें भारी नुकसान की अर्थव्यवस्था के भंवर में फंसी हुई हैं और जनता की शिकायतों का एक पहाड़ इसके सामने खड़ा है, फिर भी वर्तमान सरकार के दौर में इलेक्ट्रिक बसों की दिशा में सरकार का फैसला इनकी खरीद के अंतिम दौर में है। करीब पांच सौ तेरह करोड़ से 327 बसें खरीद कर सरकार राज्य को ग्रीन एनर्जी के तहत भविष्य की संभावना से जोड़ रही है। इससे पहले शिमला व धर्मशाला की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। बहरहाल सडक़ परिवहन के क्षेत्र में एचआरटीसी अपने आप में राज्य के सेवा क्षेत्र के अलावा पर्यटन का सेतु भी है। हाल के दिनों में इसकी चर्चा के क्षेत्र में विसंगतियां रही हैं, फिर भी एचआरटीसी हिमाचल राज्य का एक ब्रांड है, जो सीधे जनापेक्षाओं को संबोधित करता है। यह दीगर है कि एचआरटीसी की प्रबंधकीय क्षमता पर राजनीति हावी होकर ऐसे फैसले लेती रही है, जिससे सार्वजनिक परिवहन की वित्तीय स्थिति निरंतर घाटे के नीचे दबी रहती है।

अनावश्यक बस डिपो खोलकर राजनीति ने अपना कद भले ही ऊंचा कर लिया, लेकिन घाटे के सौदे में सरकारी बसें खुद पर शर्मिंदा हैं। बेशक अंतरराज्यीय बसों से एचआरटीसी की कमाई की रीढ़ दिखाई देती है, लेकिन राज्य स्तरीय व स्थानीय बस संचालन में अनावश्यक खर्चों को ढोती हुई बस सेवा कंगाल हो चुकी है। निजी बसों के मुकाबले सरकारी बसों की छवि, दक्षता, उपयोगिता व कमाई की औसत दर प्रदेश पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। राज्य व स्थानीय रूट परमिट को देखते हुए परिवहन नीति में बदलाव से निजी निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए। एचआरटीसी अपने बस अड्डों के मार्फत आय का दायरा बढ़ा सकती है। बड़े शहरों, पर्यटक व धार्मिक स्थलों के बस स्थानक अपने आप में पर्यटन परिसर साबित हों, इस हिसाब से निजी निवेश के साथ पार्टनरशिप बढ़ानी होगी। एचआरटीसी के बस अड्डे कल के मॉल होने चाहिएं तथा इनके साथ महापार्किंग की अवधारणा में प्रयास करने होंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम अगर दिल्ली में डीटीसी के साथ मिलकर बचत कर रही है, तो ऐसे आदान-प्रदान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर राज्यों के परिवहन उपक्रमों के साथ भी होने चाहिएं। मसलन एचआरटीसी चंडीगढ़-दिल्ली के बीच बस ठहराव के साथ एक रिजॉर्ट विकसित कर सकती है, जबकि पंजाब के कई रूट्स में भी ऐसी संभावना को देखना चाहिए। एचआरटीसी अगर पठानकोट से बस डिपो का संचालन कर सकती है, तो दिल्ली, चंडीगढ़ व हरिद्वार से क्यों नहीं। परिवहन की दृष्टि से एचआरटीसी को पर्यटन रूट के अलावा स्थानीय परिवहन को भी अलग से परिभाषित करना होगा। निश्चित रूप से एचआरटीसी ने कुछ धार्मिक स्थलों को हिमाचल से जोडक़र ऐसी पहल की है, लेकिन जयपुर, मसूरी, अमृतसर, कुरुक्षेत्र व जम्मू के साथ पर्यटन परिवहन की नई तस्वीर पेश करनी होगी। हिमाचल के भीतर साइट सीईंग के पैकेज अगर एचआरटीसी शुरू करे, तो धार्मिक पर्यटन से आगे नई मंजिलें तैयार होंगी। प्रदेश में परिवहन की एक परिपाटी में हम एचआरटीसी की भूमिका को देखते हैं, जबकि इसकी संपूर्णता में निजी क्षेत्र की क्षमता काफी आगे है। एचआरटीसी के दायरे में निजी क्षेत्र का निवेश अगर परिवहन के उद्देश्य व संगत से हो, तो घाटे के फेरे लाभ की स्थिति में आ सकते हैं। एचआरटीसी का बैनर उदारता व सहयोग के साथ मेहनत करे, तो जो उपयोगिता निजी वोल्वो बसें पेश कर रही हैं, उनसे कहीं आगे सरकारी उपक्रम भी खड़ा हो सकता है।

राय

परिसर में हिंसक भीड़

आज एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं, जो हमारे शिक्षण-संस्थानों के भीतर हिंसक भीड़ और उनके हमलों से जुड़ा है। यह भीड़ हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों से जुड़ी नहीं है, बल्कि एक देश के तौर पर हमें कलंकित करती है। जब मामला विदेशी छात्रों पर हिंसक हमले का सामने आता है, तब हमारे चिंता और सरोकार बढ़ जाते हैं। चूंकि दुनिया एक कुटुम्ब की तरह, आपस में अंतरंग रूप से, जुड़ रही है, लिहाजा यह उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की बुनियादी जिम्मेदारी बन जाती है कि वे अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी, सुरक्षित और स्थिर समाज के कारक और प्रोत्साहक बनें। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) का सिद्धांत और ब्रह्मवाक्य भी है। बीते शनिवार को गुजरात यूनिवर्सिटी के अहमदाबाद परिसर में एक भीड़ ने 5 विदेशी छात्रों पर तब हमला किया, जब वे रमजान के पाक महीने में नमाज पढ़ रहे थे। ऐसे हमले हमारी शिक्षा नीति के सिद्धांत, उसकी प्रतिबद्धता और आश्वासन को खंडित करते हैं। वीडियो में करीब 25 युवा छात्र विदेशी छात्रों पर हमले करते दिख रहे थे। श्रीलंका, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के 1-1 घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यकीनन यह आपराधिक घटना थी और विश्वविद्यालय के परिसर में कानून-व्यवस्था का सरासर उल्लंघन किया गया। फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कानून को हाथ में लेकर लीपापोती की कोशिश की। हालांकि दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सिर्फ यह बयान दिया कि वह गुजरात सरकार के संपर्क में है। वह और कर भी क्या सकता था? दूसरी आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया यह सामने आई कि हिंसक हमले के पीड़ितों को ही 'दोषी' करार देने की कोशिश की गई। मुद्दा यह है कि ऐसा हमला विदेश में भारतीय छात्रों के साथ भी हो सकता था। ऐसी घटनाएं होती भी रही हैं। तब हम कैसा महसूस करते हैं? हम तसल्ली देते रहे हैं कि ऐसी घटनाएं परंपरा और सिलसिलेवार नहीं हैं। ये अपवाद के तौर पर होती हैं। बेशक ये कानून का कठोर उल्लंघन हैं। ऐसी ही तसल्ली हमें विदेशी छात्रों को देनी चाहिए। हालांकि हमले के तुरंत बाद कुलपति नीरजा गुप्ता ने विदेशी छात्रों को आश्वस्त किया कि वह उन्हें एक अलग होस्टल में शिफ्ट कर देंगी। विदेशी छात्रों की सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है। यह भी कोई सौहार्द का कदम नहीं है। छात्रों को आपस में घुल-मिल कर रहना और पढऩा सीखना चाहिए, लेकिन कुलपति ने यह आत्ममंथन नहीं किया कि विदेशी छात्रों पर हमले क्यों और कैसे किए गए? विदेशी छात्र कोई भी हों, उन्हें सांस्कृतिक तौर पर संवेदनशील होना ही चाहिए। इस घटना ने साबित कर दिया है कि हमें अब भी सांस्कृतिक अनुकूलन की जरूरत है। क्या यह दायित्व विदेशी छात्रों का है? हमारे संविधान में धार्मिक आजादी का मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, लिहाजा नमाज पढऩे वालों की स्वतंत्रता और गरिमा का भी सम्मान किया जाना चाहिए था। सवाल तो यह भी है कि विश्वविद्यालय परिसर में भीड़ कहां से आई, हथियार कहां से आए? यदि भीड़ वाले भी वहीं के छात्र थे, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई? भीड़ घटनास्थल से आराम से चली कैसे गई? भारत के बहुत कम विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर 'सर्वश्रेष्ठ' आंके गए हैं। कमोबेश गुजरात यूनिवर्सिटी उनमें से एक नहीं है। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय वही हो सकते हैं, जो विचारों की स्वतंत्रता और बहस की आजादी पर आधारित शिक्षा परोसने की बात करते हैं और उन कसौटियों पर खरे भी उतरते हैं। भीड़ और उसकी हिंसा विचारों की अभिव्यक्ति और उसके विस्तार में विश्वविद्यालय के विचार को ही खत्म कर देती है। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सार्थक साबित करना है, तो हमें अपने व्यवहार, मुक्ति, जिम्मेदारी, बहुवाद, समानता और न्याय के भावों को सुनिश्चित करना होगा। करीब 50,000 विदेशी छात्र भारत में पढ़ रहे हैं।

पाठ्यक्रम में शहीद

भारत का इतिहास उन वीर बलिदानी भारत के बेटे-बेटियों से भरा है जिन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए देश हित में बलिदान दिया। यद्यपि उनमें से असंख्य ऐसे हैं जिन्हें कभी न इतिहास में स्थान मिला है, न लोक गाथाओं में, और शिक्षा जगत में तो उनको कभी स्थान मिला ही नहीं। कौन नहीं जानता कि 1857 के संग्राम में यह देखा-सुना गया कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति विफल होने के बाद गांवों में, शहरों में असंख्य लोगों को फांसी पर लटकाया। यह भी कहा जाता है कि गांवों में जब वृक्षों पर लटकाकर फांसियां दी गईं तो जितनी बड़ी शाखाएं थीं उसके साथ उतने ही व्यक्तियों को फांसी के लिए लटकाया गया। यह तो कल की बात है, 1857 से लेकर दो वर्ष तक यह दमनचक्र चला। अगर देश उसे ही नहीं जानता, तो क्या आशा रखी जा सकती है कि उससे पहले के इतिहास की सही जानकारी कभी स्वतंत्र भारत की सरकारों ने देशवासियों को दी हो। इसके पश्चात फिर ताजी घटना है कि अंडेमान की जेल, जिसे काला पानी कहते थे, वहां कितने लोग शहीद हुए, कितने बैलों की तरह कोल्हू में जोते गए। कितने लोगों को फांसी देकर बिना किसी अंतिम संस्कार के सागर में फेंक दिया गया। आज तक देश को इन सारे शहीदों की जानकारी नहीं दी गई। शहीदों की चिताओं पर मेले लगने की बात तो बहुत दूर है।

स्वतंत्रता के पश्चात जब हम लोगों ने स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, स्कूलों की दीवारों पर, हर कक्षा में शहीदों के चित्र लगाए जाते थे, यद्यपि उनकी संख्या सीमित थी। शहीदों के दिन मनाए जाते थे और पाठ्यक्रम में भी इन ज्ञात-अज्ञात वीरों की कहानियां पढ़ाई जाती थीं। बंग भंग आंदोलन जो 1905 से लेकर 1911 तक चला और फिर कलकत्ता से चलकर दिल्ली राजधानी बनाई गई, उस बंग भंग आंदोलन में खुदीराम, कन्हाई, नरेंद्र जैसे कितने वीर हाथ में गीता लिए अंग्रेज सरकार से जूझते हुए फांसी पर चढ़ गए। उनके संबंध में भी देशवासी अधिक नहीं जानते। बहुत दूर की बात क्या की जाए, अमृतसर से दो बेटे 1906 से 1909 के बीच श्री मदनलाल ढींगरा और उसके बाद 1940 में शहीद ऊधम सिंह ने भारत में भारतीय अणख और स्वाभिमान का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह भी विश्व में अतुलनीय है, लेकिन दुखद सत्य यह है कि इन हुतात्माओं की जन्मभूमि, कर्मभूमि अमृतसर और पंजाब के लोग ही इन वीरों के विषय में कुछ नहीं जानते। यह ठीक है कि 1973 में पहले शहीद ऊधम सिंह की और उसके बाद शहीद ढींगरा की अस्थियां लंदन की पैटन विले जेल से भारत लाई गईं। उनको उचित सम्मान भी दिया गया, पर मदनलाल ढींगरा के साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी सरकार ने उसकी अपनी ही जन्मभूमि अमृतसर में उसको कोई स्थान नहीं दिया। उसका स्मारक नहीं बना और लंबे संघर्ष के बाद जो अब बनाया जा रहा है, वहां भी भवन तो बन गया, लेकिन उसकी आत्मा ढींगरा से संबद्ध साहित्य इंग्लैंड में उसके बलिदान के चिन्ह आज तक भारत नहीं लाए गए, यद्यपि सरकारों को बार-बार आग्रह किया, जगाने का प्रयास किया, पर त्रेता में एक कुंभकरण था, आज हर सरकार में, हर विभाग में कुंभकरण से भी बड़े कुंभकरण विद्यमान हैं। कई अन्य शहीद भी सम्मान से वंचित हैं। हम 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु का शहीदी दिवस मनाने जा रहे हैं। शहीदों को पाठ्यक्रम में स्थान मिले, यह उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

लक्ष्मीकांता चावला

विचार

भारत की प्राचीन जल संस्कृति को जीवंत करें

ललित गर्ग

जल प्रदूषण एवं पीने के स्वच्छ जल की निरन्तर घटती मात्रा को लेकर बड़े खतरे खड़े हैं। धरती पर जीवन के लिये जल सबसे जरूरी वस्तु है, जल है तो जीवन है। जल ही किसी भी प्रकार के जीवन और उसके अस्तित्व को संभव बनाता है। जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन को यह बनाये रखता है। पीने, नहाने, ऊर्जा उत्पादन, फसलों की सिंचाई, सीवेज के निपटान, उत्पादन प्रक्रिया आदि बहुत उद्देश्यों को पूरा करने के लिये स्वच्छ जल बहुत जरूरी है। जिन पाँच तत्वों को जीवन का आधार माना गया है, उनमें से एक तत्व जल है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव एवं जीव-जन्तुओं के अलावा जल कृषि के सभी रूपों और अधिकांश औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं के लिये भी बेहद आवश्यक है। परंतु आज पूरी दुनिया जल-संकट के साए में खड़ी है। अनियोजित औद्योगीकरण, बढ़ता प्रदूषण, घटते रेगिस्तान एवं ग्लेशियर, नदियों के जलस्तर में गिरावट, पर्यावरण विनाश, प्रकृति के शोषण और इनके दुरुपयोग के प्रति असंवेदनशीलता पूरे विश्व को एक बड़े जल संकट की ओर ले जा रही है। इन सभी समस्याओं से दुनिया को अवगत कराने एवं सबको जागरूक करने के लिए 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। आप सोच सकते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन काल में कितने पानी का उपयोग करता है, किंतु क्या वह इतने पानी को बचाने का प्रयास करता है?

दुनिया की आबादी आठ अरब से अधिक हो चुकी है। इसमें से लगभग आधे लोगों को साल में कम से कम एक महीने पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण 2000 से बाढ़ की घटनाओं में 134 प्रतिशत वृद्धि हुई है और सूखे की अवधि में 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पानी के संरक्षण और समुचित उपलब्धता को सुनिश्चित कर हम पर्यावरण को भी बेहतर कर सकते हैं तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं। पैकेट और बोतल बन्द पानी आज विकास के प्रतीकचिह्न बनते जा रहे हैं और अपने संसाधनों के प्रति हमारी लापरवाही अपनी मूलभूत आवश्यकता को बाजारवाद के हवाले कर देने की राह आसान कर रही है। विशेषज्ञों ने जल को उन प्रमुख संसाधनों में शामिल किया है, जिन्हें भविष्य में प्रबंधित करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। सदियों से निर्मल जल का स्त्रोत बनी रहीं नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, जल संचयन तंत्र बिगड़ रहा है, और भू-जल स्तर लगातार घट रहा है।

धरती पर सुरक्षित और पीने के पानी के बहुत कम प्रतिशत के आंकलन के द्वारा जल संरक्षण या जल बचाओ अभियान हम सभी के लिये बहुत जरूरी हो चुका है। औद्योगिक कचरे की वजह से रोजाना पानी के बड़े स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। जल को बचाने में अधिक कार्यक्षमता लाने के लिये सभी औद्योगिक बिल्डिंगें, अपार्टमेंट्स, स्कूल, अस्पतालों आदि में बिल्डरों के द्वारा उचित जल प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिये। पीने के पानी या साधारण पानी की कमी के द्वारा होने वाली संभावित समस्या के बारे में आम लोगों को जानने के लिये जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये। जल की बर्बादी के बारे में लोगों के व्यवहार को मिटाने के लिये इसकी त्वरित जरूरत है।

इसी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में जल सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें सभी के लिए जल और स्वच्छता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। पानी धरती पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधारभूत आवश्यकता है। आबादी में वृद्धि के साथ पानी की खपत बेतहाशा बढ़ी है, लेकिन पृथ्वी पर साफ पानी की मात्रा कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और धरती के बढ़ते तापमान ने इस समस्या को गंभीर संकट बना दिया है। इस सम्मेलन में सरकार, उद्योग जगत और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए लक्ष्य तो निर्धारित किये ही जायेंगे, साथ ही आम लोगों को पानी बचाने के मुहिम से जोड़ने के लिए भी कारगर कार्ययोजना बनाने पर विचार होगा। दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत भी जल संकट का सामना कर रहा है। वैश्विक जनसंख्या का 18 प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता है, लेकिन चार प्रतिशत जल संसाधन ही हमें उपलब्ध है।

भारत में जल-संकट की समस्या से निपटने के लिये प्राचीन समय से जो प्रयत्न किये गये है, वे दुनिया के लिये मार्गदर्शक हैं। देश के सात राज्यों के 8220 ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधनों के लिए अटल भूजल योजना चल रही है। स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में चलने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। साथ ही, नल से जल, नदियों की सफाई, अतिक्रमण हटाने जैसे प्रयास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं। जल संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में राज्यों के जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था। अब यह सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाएगा। इसके उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उचित ही रेखांकित किया कि सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा तथा जल संरक्षण एवं उपयोग किये गये पानी को फिर से इस्तेमान में लाने के उपाय करने होंगे। हमारे यहां जल बचाने के मुख्य साधन है नदी, ताल एवं कूप। इन्हें अपनाओं, रक्षा करो, अभय दो, इन्हें मरुस्थल के हवाले न करो। अन्तिम समय यही तुम्हारे जीवन और जीवनी को बचायेंगे। ख्यात पर्यावरणविद अनुपम मिश्र तो 'अब भी खरे है तालाब' कहते कहते स्वर्गस्थ हो गये। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व जल दिवस की मूल भावना को अपने दैनिक जीवन में उतारकर हर व्यक्ति, हर दिन जल संरक्षण का यथासंभव प्रयास करे।

गाँव के स्तर पर लोगों के द्वारा बरसात के पानी को इकट्ठा करने की शुरुआत करनी चाहिये। उचित रख-रखाव के साथ छोटे या बड़े तालाबों को बनाने के द्वारा बरसात के पानी को बचाया जा सकता है। धरती के क्षेत्रफल का लगभग 70 प्रतिशत भाग जल से भरा हुआ है। परंतु, पीने योग्य जल मात्र तीन प्रतिशत है। इसमें से भी मात्र एक प्रतिशत मीठे जल का ही वास्तव में हम उपयोग कर पाते हैं। पानी का इस्तेमाल करते हुए हम पानी की बचत के बारे में जरा भी नहीं सोचते, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश जगहों पर जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। जल का संकट एवं विकट स्थितियां अति प्राचीन समय से बनी हुई है। इसी कारण राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आदि प्रांतों में जल संरक्षण के लिये नाड़ी, तालाब, जोहड़, बन्धा, सागर, समंद एवं सरोवर आदि बनाने की प्राचीन परम्परा रही है। राजा-महाराजाओं तथा सेठ-साहूकारों ने अपने पूर्वजों की स्मृति में अपने नाम को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से इन प्रदेशों के विभिन्न भागों में कलात्मक बावड़ियों, कुओं, तालाबों, झालरों एवं कुंडों का निर्माण करवाया। जहाँ प्रकृति एवं संस्कृति परस्पर एक दूसरे से समायोजित रही हैं। राजस्थान के किले तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं पर इनका जल प्रबन्धन विशेष रूप से देखने योग्य है और अनुकरणीय भी हैं। जल संचयन की परम्परा वहाँ के सामाजिक ढाँचे से जुड़ी हुई हैं तथा जल के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण के कारण ही प्राकृतिक जलस्रोतों को पूजा जाता है।

भारत में कोयले के आयात में आई तेजी ,अप्रैल-जनवरी अवधि में 212 मीट्रिक टन का हुआ इम्पोर्ट

Coal Import वर्तमान में भी देश के कई कामों के लिए भी कोयले की आवश्यकता होती है। खदानों और थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले आयात को लेकर एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड ने आंकड़े जारी किया है। इन आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जनवरी अवधि में देश में कोयला आयात 212 मीट्रिक टन हुआ।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश में कोयला आयात (Coal Import) में तेजी देखने को मिली है। एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड ने कोयला इम्पोर्ट को लेकर आंकड़े जारी किये हैं।

एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जनवरी अवधि में देश में कोयला आयात एक साल पहले की तुलना में 1.65 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 212.24 मिलियन टन (एमटी) हो गया।

पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में भारत का कोयला आयात 208.78 मीट्रिक टन था। बता दें कि एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड (Mjunction Services Ltd.) एक बी2बी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है।

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान नॉन-कोकिंग कोयले के आयात की मात्रा 136.47 मीट्रिक टन थी। यह पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के दौरान आयात 136.90 मीट्रिक टन से थोड़ा कम है।

अप्रैल-जनवरी 2023-24 के दौरान कोकिंग कोयले का आयात 47.32 मीट्रिक टन था। यह वित्त वर्ष 23 की अप्रैल-जनवरी अवधि में दर्ज 46.09 मीट्रिक टन से अधिक है।

मेजर और नॉन-मेजर पोर्ट के माध्यम से जनवरी में कोयला आयात भी बढ़कर 19.81 मीट्रिक टन हो गया। यह पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने में 16.97 मीट्रिक टन से अधिक था।

जनवरी में कुल आयात में से गैर-कोकिंग कोयले का आयात 12.10 मीट्रिक टन था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में जनवरी में 10.01 मीट्रिक टन आयात किया गया था। कोकिंग कोयले का आयात 4.50 मीट्रिक टन रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने में आयात 4.74 मीट्रिक टन से थोड़ा कम है।

एमजंक्शन सर्विसेज के एमडी और सीईओ विनय वर्मा ने कहा कि हाल के हफ्तों में भारत में आयातित कोयले की मांग कमजोर हुई है। खदानों और थर्मल पावर प्लांट में घरेलू कोयले की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए हमें उम्मीद है कि यह प्रवृत्ति मार्च में भी जारी रहेगी।

सरकार के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जनवरी अवधि में देश का कोयला उत्पादन 2022-23 में इसी अवधि के दौरान 698.99 मीट्रिक टन से बढ़कर 784.11 मीट्रिक टन हो गया।

डिजिटल पेमेंट बढ़ाने में UPI ने निभाई अहम भूमिका, फरवरी 2024 में 18.2 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन

UPI Transactions डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। डिजिटल भुगतान में यूपीआई एक क्रांति लेकर आया है। पिछले महीने यानी कि फरवरी 2024 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिये 18.2 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। हर महीने यूपीआई पेमेंट ट्रांजेक्शन की संख्या में तेजी देखने को मिल रही है।

नई दिल्ली। देश में डिजिटल क्रांति के बाद यूपीआई (UPI) ट्रांजेक्शन का चलन तेजी से बढ़ा हैं। देश में फरवरी 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से 122 करोड़ ट्रांजेक्शन के साथ 18.2 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया।

यह ट्रांजेक्शन जनवरी 2024 की तुलना में कुछ कम रहा। जनवरी में 121 करोड़ ट्रांजेक्शन के साथ 18.4 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था। एनपीसीआई (NPCI) ने बताया कि देश में रोजाना औसतन 40 हजार करोड़ से 80 हजार करोड़ रुपये का यूपीआई ट्रांजेक्शन होता है।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि ऑनलाइन पेमेंट के दो अन्य साधन एनईएफटी (NEFT) और आरटीजीएस (RTGS) के जरिये भी ऑनलाइन पेमेंट हुए हैं। इनमें से एनईएफटी में औसत लेनदेन 33.85 लाख करोड़ रुपये और आरटीजीएस में 146 लाख करोड़ रुपये था।

इंटरनेट बैंकिंग से 91.24 लाख करोड़ रुपये और मोबाइल बैंकिंग से 28.16 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। बता दें कि भारत आज दुनिया के लगभग 46 फीसदी डिजिटल लेनदेन (2022 के आंकड़ों के अनुसार) के लिए जिम्मेदार है।

यूपीआई ट्रांजेक्शन में तेजी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मार्च महीने की शुरुआत में बताया कि भारत में डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 2023 में 80 प्रतिशत के करीब पहुंच गई है। यह देश में मॉर्डन पेमेंट सिस्टम के विकास की रूपरेखा को दर्शाता है।

भारत में रिटेल डिजिटल पेमेंट वित्तीय वर्ष 2012-13 में 162 करोड़ लेनदेन से बढ़कर 2023-24 (फरवरी 2024 तक) में 14,726 करोड़ से अधिक लेनदेन हो गया है। इसका मतलब है कि 12 वर्षों में लगभग 90 गुना वृद्धि हुई है।

यूपीआई भारत की मोबाइल-बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। यह ग्राहकों को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) का उपयोग करके चौबीसों घंटे तुरंत पेमेंट करने की सुविधा देती है।

यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, 2024 में 3 कटौती का जताया अनुमान

US Fed Policy Meet अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। फेड रिजर्व ने अपनी पॉलिसी समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने 2024 के अंत तक में 3 कटौती का अनुमान जताया है। फेड ने ब्याज दरों को 5.25 से 5.50 फीसदी पर स्थिर रखा है।

नई दिल्ली। अमेरिका के फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) की दो दिवसीय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में ब्याज दरों को लेकर कई फैसले लिये गए हैं। फेड रिजर्व ने बताया कि उन्होंने सर्वसम्मति के साथ बेंचमार्क ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि ब्याज दर 5.25 से 5.50 फीसदी पर स्थिर रहेगी।

बता दें कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने जुलाई से प्रमुख ब्याज दरों को 23 वर्ष के उच्चतम स्थिर पर बनाए रखा है। हालांकि फेड मे उम्मीद जताई है कि 2024 के अंत में ब्याज दरों में 3 कटौती की जा सकती है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल (Federal Reserve Chair Jerome Powell) ने कहा कि हालिया महंगाई दर की वजह से ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, केंद्रीय बैंक साल के अंत में तीन ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका में आर्थिक विकास जारी रहेगा। फेड ने नए त्रैमासिक आर्थिक अनुमान जारी किये हैं। इन अनुमान को लेकर कई अधिकारियों ने अनुमान जताया है कि इस वर्ष इकोनॉमी में 2.1 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। वहीं 2024 के अंत में बेरोजगारी दर भी 4 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है। जेरोम पॉवेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है पर हम उसे 2 फीसदी तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में बेरोजगारी दर को भी कम करने के लिए फेड द्वारा कदम उठाए जा सकते हैं।

23 वर्ष के उच्चतम स्तर पर ब्याज दरें

यूएस फेड (US Fed) ने ब्याज दरों को 22 साल के उच्चतम स्तर पर बनाए रखा है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि देश की आर्थिक गतिविधियां सही दिशा में बढ़ रही है।

एनपीएस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए बचे हैं केवल कुछ दिन, जल्द निपटा लें ये काम

रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें निवेशक को एक समय तक निवेश करना होता है और रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। एनपीएस अकाउंट होल्डर को 31 मार्च 2024 से पहले अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को डिपॉजिट करना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनका अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

नई दिल्ली। एनपीएस अकाउंट होल्डर को 31 मार्च 2024 से पहले अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को डिपॉजिट करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इसके अलावा उन्हें अकाउंट में मिल रही सभी सुविधाएं भी बंद हो जाएगी। रिटायरमेंट के बाद भी इनकम को जारी रखने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें निवेशक को एक निश्चित समय तक निवेश करना होता है। निवेश की राशि पर सरकार द्वारा ब्याज भी दिया जाता है।

एनपीएस निवेशक की उम्र जब 60 वर्ष की हो जाती है तो उन्हें एनपीएस फंड से 60 फीसदी की राशि मिल जाती है। बाकी बची 40 फीसदी की राशि उन्हें पेंशन के तौर पर हर महीने मिलती है। बता दें कि अगर एनपीएस निवेशक एक वित्त वर्ष के भीतर अपने एनपीएस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट नहीं करता है तो इनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। निवेशक को एक कारोबारी साल में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होता है। एनपीएस अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए यूजर को जुर्माने का भुगतान करना होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप एनपीएस के इनएक्टिव अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करें।

अकाउंट को एक्टिव कैसे करें

स्टेप 1: यूजर को सबसे पहले एनपीएस वेबसाइट (https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/nps.aspx) पर जाकर पीआरएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना होगा।

स्टेप 2: इसके बाद My account पर जाकर Unfreeze account के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।

स्टेप 3: अब स्क्रीन पर शो हो रहे जरूरी जानकारी को दर्ज करना होगा और लेट फीस की पेमेंट करनी होगी।

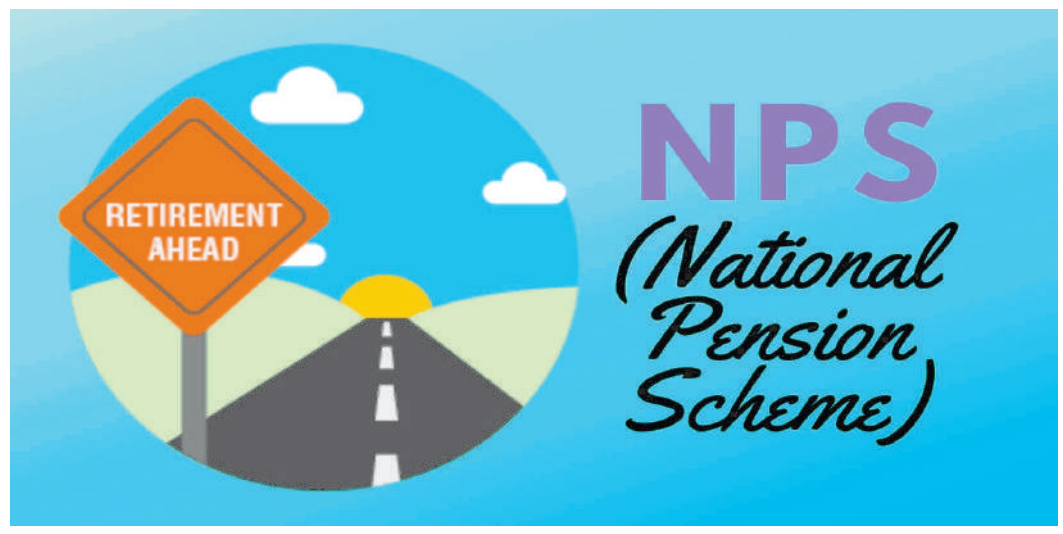

स्टेप 4: आप जैसे ही लेट फीस और मिनिमम बैलेंस का भुगतान करने के बाद अकाउंट एक्टिव हो जाएगा।

कितनी देनी होती है पेनल्टी

इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए यूजर को 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी देनी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर 3 साल से एनपीएस अकाउंट बंद है और उसे दोबारा एक्टिव करने के लिए यूजर को 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 150 रुपये का जुर्माना और 3 साल का न्यूनतम राशि 1,500 रुपये देना होगा। यानी कि यूजर को कुल 1,650 रुपये का भुगतान करना होगा।

मार्च खत्म होने में बचे हैं केवल कुछ दिन, जल्दी निपटा लें ये काम, नहीं मिलेगा दोबारा मौका

चालू वित्त वर्ष खत्म होने और अप्रैल का महीना शुरू होने में अब बस कुछ दिन का समय बचा है। ऐसे में 31 मार्च के अंत तक कुछ जरूरी वित्तीय कामों को निपटाना आवश्यक है। दरअसल 31 मार्च 2024 तक कई फाइनेंशियल कामों की आखिरी डेट है। अगर इन कामों को नहीं किया तो भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2023-24 में अब बस कुछ दिन ही बचे हैं। अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। अगले महीने से नया वित्त वर्ष शुरू होगा, इस लिहाज से मार्च का महीना काफी महत्वपूर्ण है। इस महीने कई वित्त कामों को निपटाना जरूरी है। अगर इन कामों को मार्च के बचे दिनों में नहीं करते हैं तो भविष्य में नुकसान हो सकता है।

आज हम आपको उन वित्त कामों के बारे में बताएंगे जिसकी डेडलाइन 31 मार्च 2024 है।

टैक्स सेविंग की जानकारी

जिन करदाता ने ओल्ड टैक्स रिजीम (OLD Tax Regime) सेलेक्ट की है और वो टैक्स बचाना चाहते हैं तो उनके पास टैक्स सेविंग प्लान (Tax Saving Plan) में निवेश करने का आखिरी मौका है। वह 31 मार्च 2024 तक किसी भी टैक्स सेविंग प्लान में निवेश करके टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत कई स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। प्रोविडेंट फंड (PPF), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS और टर्म डिपॉजिट (FD) जैसे कई टैक्स सेविंग प्लान है, जिसमें निवेश करके करदाता टैक्स बचा सकते हैं।

अपडेटेड आईटीआर फाइलिंग

टैक्सपेयर को अपडेट इनकम रिटर्न दाखिल (deadline to file an updated income tax return for FY21) करना का आखिरी मौका है। करदाता को यह काम 31 मार्च 2024 से पहले निपटा लेना चाहिए।

अगर टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं या फिर इनकम की कोई जानकारी नहीं दी है तो उनके पास आखिरी मौका है।

टीडीएस फाइलिंग

टैक्सपेयर्स को टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS Certificate) जारी करना होगा। इसमें उन्हें विभिन्न धारा द्वारा काटे गए टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) की जानकारी देनी होगी। करदाता को फाइलिंग चालान स्टेटमेंट (Filling Chalan Statement) की भी जानकारी देनी होगी।

मिनिमम बैलेंस मेंटेन

पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में निवेश करने वाले निवेशक को 31 मार्च 2024 से पहले अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना होगा। अगर वह वित्त वर्ष के भीतर न्यूनतम राशि डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट 1 अप्रैल 2024 से फ्रीज हो जाएगा।

बता दें कि अगर अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाता है तो फिर निवेशक को टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) के साथ बाकी लाभ भी नहीं मिलेंगे। अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए यूजर को 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी और न्यूनतम राशि डिपॉजिट करना होगा।

फास्टैग केवाईसी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग केवाईसी (FASTag KYC) को अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 दी है। जिन फास्टैग यूजर ने अभी तक केवाईसी नहीं किया है उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लेना चाहिए। जो यूजर फास्टैग केवाईसी नहीं करवाते हैं वह 31 मार्च के बाद से फास्टैग को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे।

US Fed के ऐलान के बाद चमक गई भारतीय करेंसी, डॉलर के मुकाबले इतने पैसे चढ़ा रुपया

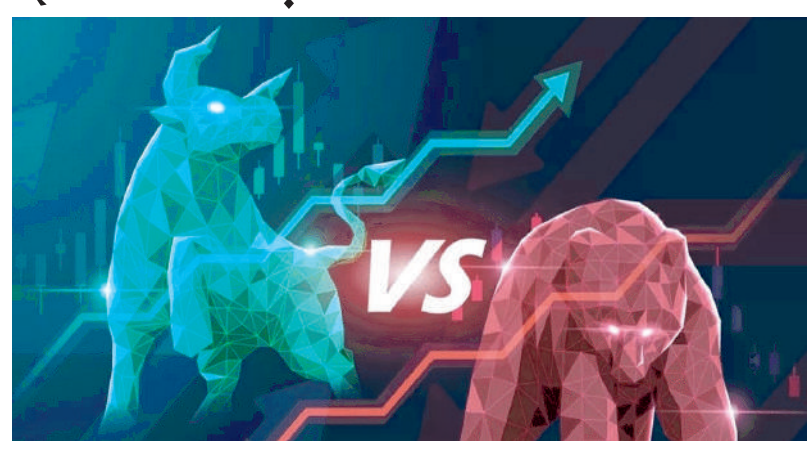

गुरुवार के कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे उछलकर खुला है। यूएस फेड ने ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिये हैं। इसके बाद डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी के साथ कारोबार करने लगा। आज इंटरबैंक विदेशी मुद्रा में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे बढ़कर 83.05 पर पहुंच गया। पढ़ें पूरी खबर..

नई दिल्ली। डॉलर के मुकाबले रुपये में गुरुवार के कारोबारी सत्र में मजबूती देखी जा रही है। आज रुपया 14 पैसे रिकवर कर शुरुआती कारोबार में 83.05 पर ट्रेड कर रहा है।

भारतीय रुपये में तेजी की वजह यूएस फेड (US Fed) द्वारा ऐलान माने जा रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस साल तीन दरों में कटौती के संकेत दिये हैं।

डॉलर और रुपये के बीच कारोबार

इंटरबैंक विदेशी मुद्रा पर रुपया ग्रीनबैक के मुकाबले 83.19 के पिछले बंद स्तर की तुलना में 83.07 पर मजबूत खुला। यशुरुआती सौदों में स्थानीय इकाई 83.08 से 83.04 के दायरे में रही।

आज सुबह 9.25 बजे रुपया प्रति डॉलर 83.05 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद के मुकाबले 14 पैसे की बढ़त दर्शाता है। डॉलर में आई तेजी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच यूएस फेड नीति की घोषणा से पहले बुधवार को यह दो महीने के निचले स्तर 83.19 पर बंद हुआ।

डॉलर इंडेक्स का क्या है हाल?

दुनिया की बड़ी करेंसी के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की मजबूती बताने वाला डॉलर इंडेक्स 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 103.22 पर बना हुआ है। कच्चे तेल में आज फिर तेजी देखी जा रही है और यह 0.63 प्रतिशत बढ़कर 86.49 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर है।

भारतीय शेयर बाजार मे कैसा रहा कारोबार?

आज शेयर मार्केट (Share Market Today) में तेजी देखने को मिला है। बीएसई सेंसेक्स 538.01 अंक बढ़कर 72,639.70 अंक पर खुला। निफ्टी 162.90 अंक बढ़कर 22,002 पर पहुंच गया। एफआईआई की ओर से बुधवार को शेयर बाजार में 2,599.19 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची।

जहां से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खड़े होंगे वहां से मैं उम्मीदवार बनूंगा: अक्षय कुमार

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेश्वर : मैं उस सीट से खड़ा होगि जहां से मुख्यमंत्री नबीन पटनायक नामांकित करेंगे , मैं उसके खिलाफ दौड़ूंगा । ऐसी घोषणा नव निर्माण किसान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अक्षय कुमार ने की है । अक्षय कुमार ने आज अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की ।उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक ने राज्य के सभी वर्गों के लोगों के लिए विभिन्न लाभों की घोषणा की। उन्होंने प्रदेश के किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं की । अक्षय कुमार ने कहा, इसलिए नवनिर्माण किसान संगठन उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा । अक्षय कुमार ने कुछ दिन पहले ही कुछ विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवारी का भी ऐलान किया है । इस बार नवगठित किसान संगठन पहली बार राजनीतिक मैदान में उतरा है ।

वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट पर है कई रहस्यों का भंडार...

परिवहन विशेष न्यूज

बनारस को दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है और कहा जाता है कि, इस देश में भगवान भोलेनाथ का वास है। बनारस शहर को वाराणसी और काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपनी प्राचीन मंदिरों और संकरी गलियों में एक इतिहास को छिपाए बैठा है और इसके साथ ही यह शहर न जाने कितनी संस्कृतियों और सभ्यताओं के लुप्त होने का साक्षी बना हो।

इस शहर के बीचों बीच गंगा नदी प्रवाहित होती है और गंगा के किनारे बसे हुए सभी घाट अपनी एक अलग ही कहानी को बता रहे हैं। काशी के इन्हीं घाटों में से एक है प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट और इस घाट का सनातन संस्कृति में एक अलग ही महत्व है। काशी का यह घाट अपनी विचित्रताओं की वजह से प्रसिद्ध है और इसकी आध्यात्मिक मान्यताऐं भी अपने आप में विशेष हैं। अगर आप काशी के मणिकर्णिका घाट के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज के इस लेख में हम आपको इस घाट के इतिहास और इससे जुड़े हुए सभी रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे।

मणिकर्णिका घाट का इतिहास

मणिकर्णिका घाट सबसे प्राचीन शहर वाराणसी का सबसे प्राचीन घाट है और हिन्दू संस्कृति में इस घाट को अन्य घाटों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि, जिस भी इंसान का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट में किया जाता है उसे तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि, मणिकर्णिका में आकर मृत्यु का दर्द भी समाप्त हो जाता है। इस घाट का उल्लेख 5 वीं शताब्दी के एक गुप्त लेख में मिलता है और हिन्दू धर्म में भी इसका सम्मान किया जाता है।

मणिकर्णिका घाट की पौराणिक कथा

मणिकर्णिका घाट में पौराणिक काल से ही शवों के अंतिम संस्कार की कथाएं प्रचिलित हैं और इन कथाओं में ही इसके नाम करण की भी कहानी छिपी हुई है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि, जब देवी सती ने अपने पिता के द्वारा किए गए अपमानों ने दुखी होकर अग्नि कुंड में समा गई थी तब भगवान भोलेनाथ उनके जलते हुए शरीर को अपने हाथों में उठाकर हिमालय की तरफ चल पड़े। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने माता सती के शरीर के दुर्दशा को देखते हुए अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस स्थान पर माता सती की बालियां गिरी थी जिसकी वजह से इस स्थान का नाम मणिकर्णिका हो गया। संस्कृत में कान की बालियों को मणिकर्ण के नाम से जाना जाता है और इस वजह से इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया।

मणिकर्णिका घाट पर मौजूद कुएं का रहस्य

मणिकर्णिका घाट पर एक कुआं पर है और इस कुएं का संबंध भगवान विष्णु से है, कहा जाता है कि, इस कुएं का निर्माण भगवान विष्णु ने किया था। कहा जाता है कि, भगवान शिव माता पार्वती के साथ वाराणसी आए थे और इस स्थान पर विष्णु भगवान के कहने पर इन्होंने एक कुआं खोदा था और उस कुएं के पास भगवान शिव स्नान कर रहे थे तब उनके कान की बाली गिर गई थी। इसके साथ ही दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि, जब भगवान भोलेनाथ तांडव कर रहे थे तब उनके कान का कुंडल इसी स्थान पर गिर गया था और कुएं का निर्माण हो गया था।

24 घंटे बराबर होता है अंतिम संस्कार

मणिकर्णिका घाट ओर आदिकाल से चिताऐं जल रही हैं और कहा जा रहा है कि, जिस दिन चिताऐं जलना बंद हो जाएंगी उस दिन प्रलय आ जाएगी और इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। इस घाट की प्रसिद्धि का आलम कुछ इस प्रकार है कि, लोग देश-विदेश से इन जलती हुई चिताओं को देखने के लिए आते हैं। वास्तव में वाराणसी का यह घाट अपनी अनोखी संस्कृत और रिवाजों को समेटे हुए है और इसी वजह से देश भर में इसकी प्रसिद्धि है।

काशी की प्रसिद्ध चिता भस्म होली मणिकर्णिका घाट पर खेली गई...

देश के अलग-अलग हिस्सों में होली से जुड़ी कईं मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित हैं। आमतौर पर होली रंग-गुलाल से खेली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जगह ऐसी भी हैं जहां श्मशान में चिता की राख से होली खेलने की परंपरा है। ये जगह है काशी का मणिकर्णिका घाट। और श्मशान को मसान भी कहते हैं इसलिए इस परंपरा को मसान होली के नाम से जाना जाता है। आगे जानिए मसान होली से जुड़ी खास बातें। क्यों खेलते हैं काशी में मसान होली? काशी को भगवान शिव का घर कहा जाता है। मान्यता है कि देवी पार्वती से विवाह करने के बाद शिवजी उन्हें काशी लेकर आए। उस दिन रंगभरी एकादशी थी। शिवजी के विवाह की खुशी में अगले दिन मणिकर्णिका घाट पर शिवजी के गणों व भूत-प्रेतों ने श्मशान में चिता की राख से होली उत्सव मनाया। इस उत्सव में शिवजी भी शामिल हुए। तभी से यहां हर साल मसान होली खेली जाती है। लोगों

का मानना है कि आज भी भगवान शिव मसान में गुप्त रूप से आते हैं। इस बार मसान होली 21 मार्च, गुरुवार को खेली गई। चिता भस्म से ही क्यों खेलते हैं होली? काशी के मणिकर्णिका घाट चिता भस्म से होली खेलने की परंपरा के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये संसार नश्वर है यानी एक दिन नष्ट होने वाला है। ये दुनिया एक दिन भस्म यानी राख में बदल जाएगी। यहां रहने वाले हर प्राणी का भी यही हाल होगा। चिता भस्म से होली खेलने का अर्थ ये है है कि इस दुनिया और अपने जीवन से अधिक मोह न रखें क्योंकि ये सबकुछ एक दिन राख में बदल जाएगा। क्यों खास है काशी का मणिकर्णिका घाट? काशी का मणिकर्णिका घाट बहुत ही प्राचीन है। अनेक धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, एक बार देवी पार्वती का कर्ण फूल (कान में पहनने का आभूषण) यहां एक कुंड में गिर गया था। जिसे बाद में भगवान शिव ने ढूंढ लिया। देवी पार्वती के कान का आभूषण गिरने के कारण ही इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। एक बात और जो इस घाट को विशेष बनाती है वो ये कि महादेव ने इसी स्थान पर देवी सती का अग्नि संस्कार किया था, इसलिए इसे महाश्मसान भी कहते हैं।

एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनने वाला शहर, आइए जानते हैं क्यों और कैसे ?

परिवहन विशेष न्यूज

आज प्रयागराज (इलाहाबाद) को अवध के जिलों में नहीं गिना जाता, जबकि उसी से अलग होकर बने जिलों फतेहपुर और कौशांबी के बगैर उनकी गिनती को पूरा नहीं माना जाता है। बात ऐसी है कि मुगलों और नवाबों के उतार चढ़ाव, इन दोनों दरबारों की खींचतान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते सर्वोच्च प्रभाव के दौर से ही इलाहबाद का अवध के अंदर बाहर होना उसकी नियति रही है। इसके पीछे इसकी बेहद महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति थी, जिसके कारणवश तीनों पक्ष उसे हथियाने के चक्कर में रहते थे।

बात उन दिनों की है जब भारत के दो बड़े सत्ता केंद्रों- दिल्ली और कलकत्ता के बीच आना जाना इलाहाबाद से ही होकर संभव था। जिसके कारण 22-23 अक्टूबर, 1764 की बक्सर की लड़ाई में कंपनी की अप्रत्याशित जीत के बाद अवध के भविष्य एवं सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करने वाले दोनों महत्वपूर्ण समझौते इलाहाबाद में ही हुए। 12 अगस्त, 1765 को हुई पहली संधि पर कंपनी की ओर से उसके बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि को इतिहासकार 'भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक' और 'ब्रिटिश बाबर' कहते हैं। अन्य दो हस्ताक्षरकर्ता मुगल बादशाह शाहआलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। इस संधि के तहत कंपनी ने इलाहाबाद के किले सहित कड़ा परगने का बड़ा इलाका (जो अब फतेहपुर जिले का हिस्सा है) अवध से छीनकर मुगलों को दे दिया था। कुछ ही दिनों बाद 16 अगस्त, 1765 को क्लाइव ने शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की दूसरी संधि की थी। इसके तहत उसने कंपनी के लिए समूचे अवध में बिना कोई कर दिए निर्बाध व्यापार की आजादी तो हासिल की ही साथ ही सूबे की सुरक्षा का जिम्मा उठाने के बहाने से उसके ही खर्च पर लखनऊ में बड़ी सेना रखने का अधिकार भी हासिल कर लिया था। हालांकि नवाब शुजाउद्दौला से उनका इकबाल ही छीना था, नवाबी बनी रहने दी थी। जबकि बक्सर में कंपनी ने जिस तरह बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह के साथ शुजा की अजेय मानी जाने वाली सेना को भी धूल चटा दी थी, वह उनसे उनकी नवाबी छीन भी सकता था।

आगे चलकर मुगलों के और बुरे दिन आ गए थे।।

1773 में कंपनी ने इलाहाबाद में अकबर के बनवाए विशाल किले को उसकी 'खरीद-बिक्री' की हैसियत तक पंहुचा दिया था।।फिर तो कंपनी बस उस किले को फुटबॉल की तरह इधर से उधर लुढ़काती रही। फिर 1775 में पचास लाख रुपयों के बदले उसे उन्हीं शुजाउद्दौला को दे दिया, जिनसे छीनकर मुगलों को दिया था। कहते हैं कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स (1772-1785) ने एक रणनीति के कारण ऐसा किया था, लेकिन 1797 में अवध के नए नवाब सआदतअली खान से संधि के बाद उसने इस किले के साथ चुनार, बनारस और गाजीपुर समेत अवध के लगभग आधे इलाके हथिया लिए थे। परंतु 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम के वक्त अवध की तरह इलाहाबाद ने भी कंपनी को साँस नहीं लेने दी। उसके सेनानायकों ने बाजी पूरी तरह पलट दी, तो भी अरसे तक अवध को लेकर उसके अंदेशे कम नहीं हो पाए। तब परेशान होकर कंपनी ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत की सत्ता उससे छीन लेने की घोषणा लखनऊ के बजाय इलाहाबाद में करवाई। 1 नवंबर 1858 में इलाहबाद को एक दिन के लिए देश की राजधानी बनाया और वहीं शाही दरबार भी लगाया गया । पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इस दरबार में महारानी विक्टोरिया की ओर से घोषणा पढ़ा। उसमें कंपनी के खिलाफ हथियार उठाने वाले ऐसे सभी बागियों को आम माफी दे दी गई थी, जिनका किसी अंग्रेज की हत्या में हाथ नहीं था।

इसके बाद में वायसराय लॉर्ड मिंटो (द्वितीय) ने इस दरबार की याद में उसकी जगह एक स्मारक बनवा दिया। उसमें उनके नाम पर एक पार्क भी विकसित किया गया। इस पार्क को अब महामना मदनमोहन मालवीय पार्क भी कहा जाता है। इस सिलसिले में यह जानना भी दिलचस्प है कि थोड़े दिनों के लिए ही सही, पर इलाहाबाद के खाते में उत्तर पश्चिम और संयुक्त प्रांत (आगरा और अवध) की राजधानी होने का गौरव भी शामिल है।

गुरुद्वारा बोहरी साहिब में 102 श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद तीसरी श्रृंखला के 51 श्री अखंड पाठ साहिब दोबारा शुरू किए गए और श्रद्धालुओं ने मत्था टेककर गुरु घर का आशीर्वाद

परिवहन विशेष न्यूज

अमृतसर (साहिल बेरी) ऐतिहासिक गुरुद्वारा बोहरी साहिब कोट में खालसा।इवेंट कमेटी के अध्यक्ष सविंदर सिंह संधू के नेतृत्व में 85वां विशाल होला मोहल्ला मनाया जा रहा है। इस मेले के संबंध में. अध्यक्ष सविंदर सिंह संधू ने बताया कि संगत के सहयोग से यह आयोजन हर वर्ष मनाया जाता है। उन्होंने मेले के दौरान गुरुद्वारा साहिब के रास्ते में लंगर लगाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वे लंगर लगाएं, लेकिन सड़क से हटें तो ट्रैफिक जाम न हो। उन्होंने कहा कि श्री अखंड पाठ साहिब की तीसरी श्रृंखला 23 मार्च को जारी की जाएगी। इसी प्रकार 23 मार्च, 25 मार्च और 27 मार्च तक श्री अखंड पाठ साहिब की विभिन्न श्रृंखलाओं के समापन के बाद कुल 255 श्री अखंड पाठ साहिब आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पाठ करवाने वाले परिवारों को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त सिरोपाओ भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हरभजन सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष नंबरदार, अवतार सिंह सरकारिया उपाध्यक्ष, परमिंदर सिंह संधू सचिव, कुलवंत सिंह सरकारिया महासचिव, दविंदर सिंह संधू प्रचार सचिव, जत्थेदार मेजर सिंह सरकारिया ऑडिटर, सुरजीत सिंह स्टोर कीपर, अमनदीप सिंह ख्यालिया कोषाध्यक्ष, सुखबीर सिंह सोनी पूर्व कौंसलर, हरसिमरनदीप सिंह संधू, दिलबाग सिंह संसरिया, बग्गा सिंह, मंजीत सिंह झंड, सुरजीत सिंह संधू, अवतार सिंह संधू, पाल सिंह संधू, बलदीप सिंह, हरदयाल सिंह संधू, रघबीर सिंह संधू (सभी सदस्य समिति), खुशबीर सिंह आदि मौजूद रहे।

अपील - शांति और सद्भाव के साथ मनाएं होली का त्यौहार : वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और कहा जाता है कि इससे समृद्धि और खुशियाँ आती हैं और सभी नकारात्मकता और बीमारियाँ नष्ट हो जाती हैं। इस साल होली सोमवार 25 मार्च को खेली जाएगी, जबकि होलिका दहन रविवार 24 मार्च को मनाया जाएगा।

नजदीक आ चुके होली, ईद, नवरात्र के त्यौहार तथा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकप्रिय एवं सुप्रशिद्ध वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने इस पावन अवसर पर सभी जनपद वासियों को होली एवं ईद की अग्रिम शुभकामनाएं व्यक्त कर सभी संभ्रांत लोगों से अपील करते हुए कहा कि त्योहारों को शांति और सद्भाव पूर्ण तरीके से मनाएं। होली का पर्व एक सामाजिक समरसता का पर्व है। इस पर्व को सभी व्यक्ति अपने पारस्परिक भेदभाव, शत्रुता, मत, पंत, जाति बुलाकर स्नेह के साथ होली का पर्व मनाते हैं। होली और माहे रमजान साथ - साथ हैं। इसलिए त्यौहार पर आपसी सौहार्द और शांति बनाएं रखें। होली के पर्व पर ऐसा कोई कार्य ना किया जाएं जिससे किसी की स्वतंत्रता को आघात ना किया जाएं। इसलिये जनपद के समाजसेवियों की सभी से अपील की हैं कि शांतिपूर्ण व सौहार्द पूर्ण होली एवं रमजान पर्व मनाएं क्योंकि आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के लिए आगरा का इतिहास हमेशा से अच्छा रहा है। इस परंपरा और यहां की संस्कृति एवं गंगा जमुनी तहजीब को अछून्य बनाए रखना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। सभी लोग संयम, मानवता, संवेदनशीलता, शालीनता, प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का पालन करते हुए धार्मिक भावनाओं को आहत किए बगैर तोहार को पूरे उत्साह के साथ मनाएं। सभी संभ्रांत लोगों से अपील हैं कि अपने आसपास के युवाओं के साथ बैठकर उन्हें नैतिक एवं मानवीय मूल्यों से परिचित कराएं की होली पर्व एवं माहे रमजान के दृष्टिगत होने वाले आयोजन के दौरान किसी प्रकार के मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। होली का त्यौहार आपसी भाईचारे व सौहार्द का त्योहार है। इसे आपस में मिलजुल कर मनाएं। होलिका परंपरागत ढंग से जलाएं। बिना अनुमति के डीजे ना बजाएं तथा नशा करके वाहन ना चलाएं। कपड़ा फाड़ व कीचड़ से होली ना खेलें। बल्कि रंग व गुलाल से होली का त्यौहार मनाएं। ध्यान रहें जो होली ना खेले उसे जबरन रंग ना लगाएं। किसी भी प्रकार की अभद्रता व हुड़दंग ना करें। योगीजी ने त्योहारों में धार्मिक परंपराओं और आस्था को पूरा सम्मान दिया हैं, लेकिन अराजकता स्वीकार नहीं की।

श्री खुराना ने आगे कहा कि होलिकोत्सव, रमजान, ईद, नवरोज़, चैत्र नवरात्र, राम नवमी आदि महत्वपूर्ण पर्व- त्योहारों एवं लोकसभा चुनाव के कारण अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आदि लगेंगे लेकिन उल्लास और उमंग के बीच कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है। हम सभी को त्योहारों पर शरारती तत्वों से सतत सतर्क-सावधान रहना होगा। पिछले सात साल से प्रदेश में सभी धर्म-सम्प्रदाय के पर्व-त्योहारों के आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुए हैं। इस क्रम को आगे भी

बनाये रखना होगा। पर्व-त्योहार में शासन द्वारा सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। धार्मिक परंपरा/आस्था को सम्मान दिया जा रहा हैं। अश्लील/फूहड़ गीत कतई न बजाएं। धर्मस्थलों पर रंग न डाले। छोटी सी अफवाह माहौल को बिगाड़ सकती है। इसलिए होली के पर्व पर ऐसा कोई कार्य ना किया जाएं जिससे किसी की स्वतंत्रता को आघात ना किया जाएं। आने वाले दिनों में कई त्यौहार साथ - साथ हैं इसलिए त्यौहार पर आपसी सौहार्द और शांति बनाएं रखें। त्यौहार को हम मिलजुलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। इसमें सर्व समाज की सहभागिता होनी ज़रूरी हैं। सभी स्वस्थ्य मन एवं भाईचारे के साथ त्यौहार का आनन्द उठाएं और कोई भी कार्य परम्परा से हट कर ना करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपस में ना उलझें, उसकी सुचना तत्काल पुलिस को दें। किसी समाज का त्यौहार हम सब के लिए एक हैं,चाहें वो किसी भी धर्म का हों। रमजान और होली का पर्व एक साथ पड़ने की बजह से धार्मिक सद्भाव बनाएं रखना बहुत जरूरी हैं। होली के पर्व पर ऐसा कोई कार्य ना किया जाएं जिससे किसी की स्वतंत्रता को आघात ना किया जाए। होली सभी के जीवन में रंगों और प्रेम की बहार लेकर आये। सभी लोग त्योहार को शांति पूर्ण ढंग से मनाए। होली मे रंग डालते समय इतना ध्यान रखे, ऐसे व्यक्ति पर रंग न डाले जो परहेज करता हो। यदि शरारती तत्व नशे की हालत मे शरारत करें तो उसकी सूचना पुलिस को दे। त्योहार का आंनद ले, किसी को आपके व्यवहार से तकलीफ न पहुंचे इसका विशेष रुप से ध्यान रखे। होली एक धार्मिक त्यौहार हैं। इसे पूरी दुनियां में हिंदुओं द्वारा के साथ मनाया जाता हैं। एक दूसरे के गीले शिकवे को मिटाकर हम सभी को होली के पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। होली का पर्व का प्राकृतिक सौहार्द का त्योहार है। यह भेदभाव को भुलाकर स्नेह के रंग में रंगने का पर्व हैं। साथ ही ऐसे पर्व सामाजिक समरसता को बढ़ाने का काम भी करते हैं। होली के दिन आपस में मिलजुल कर होली खेले। एक दूसरे को गुलाल लगाये और गले मिले और जो होली ना खेले उसके साथ जबरदस्ती रंग ना लगाएं। शराब पीकर गाड़ी ना चलायें। आने वाले दिनों में होली और शव ए बरात साथ - साथ हैं इसलिए त्यौहार पर आपसी सौहार्द और शांति बनाएं रखें। क़ानून और शांति व्यवस्था बनाएं रखने के लिए प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करना हर एक नागरिक का प्रथम कर्तव्य हैं। अगर किसी के साथ कोई भी आपराधिक घटना होती हैं तो उसकी तत्काल सुचना पुलिस को अवश्य देनी चाहिए। इसी विचार के साथ सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पावन होली सभी के जीवन में रंगों और प्रेम की बहार लेकर आये।

मेरठ से कुमार विश्वास, रायबरेली से नूपुर शर्मा, चौंकाने की तैयारी में भाजपा

परिवहन विशेष। एस.डी. सेठी।

भाजपा लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारी को लिस्टेड करने में खासा चौका सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश से 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मगर कुछ तुरुप के पत्ते अभी खुलने बाकी है। रहस्मयी पत्तो के शौ होते ही मुंह खुला -का खुला रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली से मेरठ तक पार्टी कई नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है।गांधी परिवार का गढ रायबरेली से बीजेपी नूपुर शर्मा को टिकट थमा सकती है। तो वहीं मेरठ से प्रख्यात कवि व नए-नए रामायण कथा वाचक अवतार में आए कुमार विश्वास को टिकट थमाने की अटकलें खासा चर्चा में है। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कट सकता है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कुल 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। जिसमें 51 यूपी के थे। लेकिन इसमें बृजभूषण, वरूण गांधी, मेनका गांधी आदि के नाम नहीं होने की वजह से कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। वैसे उत्तर प्रदेश से चारों गांधी जिनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वरूण गांधी, और मेनका गांधी अपने को अलग रखने की तैयारी में है। गुरुवार की खबर है कि पीलीभीत से वरूण गांधी ने नामांकन पत्र तो खरीद लिए है। लेकिनअभी तक तय नहीं हुआ है है वह निर्दलीय या किसी पार्टी से चुनाव लडेगें ? वहीं बृजभूषण शरण सिंह की जगह पार्टी उनके परिवार के सदस्य को टिकट दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूपी कौर कमेटी की बैठक में कुमार विश्वास के भी नाम की चर्चा हुई है।इसके अलावा रामायण सीरियल के राम अभिनेता अरूण गौविल के नाम पर भी चर्चा है। मेरठ में बीजेपी वैश्य, ब्राह्मण, ठाकुर के समीकरण को विशेष तौर पर तवज्जो दे रही है। रायबरेली से गांधी परिवार की हिलती चूलों के मद्देनजर ही नूपुर शर्मा अचानक प्रकट हुई है।उन्हें पैगंबर विवाद के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया था।उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली थी।लंबे समय तक वह ज्यादातर सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई नहीं दी गई। लेकिन पिछले कुछ समय में वह कार्यक्रमों में दिखने लगी है।सोशल मीडिया पर भी नूपुर चर्चित नाम रही है।ऐसे में बीजेपी उन्हें रायबरेली सीट से मैदान में उतार सकती है।

श्री दरबार साहिब अमृतसर ने खाद्य गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की

परिवहन विशेष न्यूज

अमृतसर (साहिल बेरी) हाल ही में नियुक्त खाद्य आयुक्त श्री बाल मुकंद शर्मा ने आज अमृतसर में खाद्य गुणवत्ता विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पंजाब में भोजन की कोई कमी नहीं है, पंजाब देश की खाद्य जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन हमें भोजन की मात्रा के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि खेत में उपज से लेकर दुकान में बिकने वाले सामान तक हमें उसकी गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम करें. इस अवसर पर उनके साथ डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सरताज सिंह, डीएम मार्कफेड गुरप्रीत सिंह व अन्य उपस्थित थे। इसके बाद श्री बालमकंद शर्मा ने अपनी पत्नी श्रीमती कंचन शर्मा के साथ श्री दरबार साहिब और श्री दुर्गियाना मंदिर में मत्था टेका और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। कैप्शनः श्री बाल मुकंद शर्मा और उनकी पत्नी श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होते हुए।

बाबा अमरनाथ यात्रा पंजीकरण 15 अप्रैल से होगा शुरू, यात्रा 29 जून से 19अगस्त तक

अमरनाथ यात्रा बाबा के भक्तो का इंतजार खत्म 29 जून से 19 अगस्त तक, यात्रा रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू सूत्र

नई दिल्ली। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए यात्रा पंजीकरण की तारीख एवम् यात्रा तिथि घोषित, उनका इंतजार हुआ खत्म। अमरनाथ यात्रा पर भारत देश के सभी शहरो से अनगिनत भक्तजन जाते है और इस वर्ष भी लाखो भक्तो के जाने की सम्भावना है यात्रा मार्ग सुगम हो गया है जिस कारण इस वर्ष से भक्तजनों के पहले से बहुत अधिक संख्या में जाने की आशा है। इस यात्रा में भक्तजनों को खाना, दवाई और पानी की सेवा भारत देश की अनगिनत महादेव सेवा समिति बैस कैंप में यात्रियों की सेवा के लिये पहुंचते हैं इसमें सभी सेवादारों का लक्ष्य है अमरनाथ यात्रा पर पहुचने वाले सभी शिव भक्तो की तन मन से सेवा करना। सभी भक्तो में यात्रा की तारीख आने से खुशी की लहर है।

जातिय आधार पर टिकिट वितरण समाज के लिए विघटनकारी, लोकतंत्र को कमजोर करने कोशिश

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत में लोकसभा चुनाव एक बड़ी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक दलों का मुख्य ध्यान होता है। इस प्रक्रिया में उन्हें अपने उम्मीदवारों के लिए टिकिट वितरण करना होता है। जातीय आधार पर राजनीतिक दलों का टिकिट वितरण एक विवादास्पद मुद्दा है, क्योंकि जातियों के आधार पर यह प्रक्रिया समाज में विभाजन और विवाद पैदा कर सकती है। जातीय आधार पर राजनीतिक दलों का टिकिट वितरण करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे मुख्य कारण होता है जनसंख्या के आधार पर जातियों की धारारूप से मतदाताओं की आंतरिक गणना करना। राजनीतिक दलों को इसका ध्यान रखना होता है ताकि वे विजय प्राप्त करने के लिए उन मतदाताओं की समर्थन प्राप्त कर सकें। दूसरा कारण हो सकता है किसी खास जाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ध्यान रखकर उन्हें टिकिट देना। इससे वे उन्हें एक आर्थिक मजबूती संघान कर सकते हैं और उनके समर्थन को प्राप्त कर सकते हैं। जातीय आधार पर टिकिट वितरण के मामले में राजनीतिक दलों को सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रक्रिया में न्याय और समानता का पालन करना चाहिए ताकि समाज में विभाजन न हो और समर्थन प्राप्त करने का मार्ग सही और उचित हो। राजनीतिक दलों को जनता के हित में सोचकर टिकट वितरण करना उनका नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिसे उन्हें स्वीकार करना चाहिए।

उडीशा की कांग्रेस सेवा दल द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्ति

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा : भुवनेश्वर: आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं । कांग्रेस मैदान में उतरने के लिए संघर्ष कर रही है । राज्य की सबसे पुरानी पार्टी बीजेपी और बिजेड़ी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं । इस बीच, कांग्रेस पार्टी की ओर से 2024 के आम चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।जिला स्तर पर आम चुनाव कार्य का प्रबंधन करने के लिए ओडिशा प्रदेश कांग्रेस सेवादल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। अधिवक्ता दुखिश्याम दास और Er मानस नाइक को पीसीसी सेवादल के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बरुण राज और श्रीकांत दाडिया सोशल मीडिया के प्रभारी होंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail .com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023